16 अक्टूबर, 2026 शुक्रवार
नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 197

अनोखे अंदाज और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर

टाइम्स ऑफ़ पीडीया

RNI No: DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email: timesofpedia@gmail.com

विश्वकप में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका से रहना होगा सावधानः अश्विन 07

पीएम मोदी ने लद्दाख को दी 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन और लोकार्पण किया, लेह एयरपोर्ट का नया टर्मिनल

- 298 किमी लंबी सड़क और देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क शामिल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लद्दाख में करीब 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने, बिजली की उपलब्धता बढ़ाने, जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। परियोजनाओं में लेह एयरपोर्ट का नया यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दरचा सड़क, नौ मेगावाट की हानू लघु जलविद्युत परियोजना और बिजली ट्रांसमिशन लाइन प्रमुख हैं।

इसके अलावा, सिंधु घाट पर देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क विकसित करने तथा 40 गांवों में जलाशय बनाने की परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले लद्दाख में विकास कार्यों को गति मिलने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं मजबूत होने की उम्मीद है।

निम्मू-पदुम-दरचा सड़क परियोजना लद्दाख में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। करीब 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। वहीं, लेह एयरपोर्ट के नए यात्री टर्मिनल से हवाई यात्रा से जुड़ी सुविधाओं को विस्तार मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क और हवाई संपर्क से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी लाभ मिल सकता है।

जलाशयों से किसानों को मिलेगा लाभ

जल संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट अमृत हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में 40 जलाशय बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य उपलब्ध पानी को संग्रहित कर जरूरत के समय इस्तेमाल करना है। लद्दाख में मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सालभर पानी की उपलब्धता एक समान नहीं रहती। बर्फ पिघलने और ग्लेशियरों से कुछ समय पर्याप्त पानी मिलता है, लेकिन खेती के लिए जरूरी बुवाई के दौरान कई क्षेत्रों में पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में जलाशयों में पानी जमा करने से सिंचाई की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सहारा देने में सहायता मिल सकती है। जल संग्रहण की व्यवस्था क्षेत्र में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में भी उपयोगी साबित हो सकती है।

पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क से बचेगी प्राचीन विरासत

लेह के सिंधु घाट पर प्रस्तावित पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का उद्देश्य प्राचीन शैलचित्रों और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियों को संरक्षित करना है। लद्दाख में अनेक स्थानों पर चट्टानों पर मनुष्यों, वन्यजीवों और विभिन्न प्रतीकों की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये कलाकृतियां क्षेत्र के प्राचीन इतिहास, संस्कृति और मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। संरक्षण पार्क के माध्यम से इन ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान से बचाने और उनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। इससे सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

बिजली उत्पादन और आपूर्ति होगी मजबूत

लद्दाख में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नौ मेगावाट की हानू लघु जलविद्युत परियोजना और 66 केवी की डबल-सर्किट दाह-हानू-खलत्सी ट्रांसमिशन लाइन भी परियोजनाओं में शामिल हैं। जलविद्युत परियोजना से स्थानीय जल संसाधनों के जरिए बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि नई ट्रांसमिशन लाइन बिजली आपूर्ति नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता बेहतर करने में मदद करेगी। इन परियोजनाओं के जरिए लद्दाख में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ जल संरक्षण, ऊर्जा उपलब्धता और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। इनके प्रभावी संचालन से स्थानीय आबादी, किसानों और पर्यटन गतिविधियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

संक्षिप्त वार्ता

झोटा हत्याकांडः पंजाब में बंद का व्यापक रहा असर

चंडीगढ़। नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में आज पंजाब बंद का आह्वान किया गया, जिसका मानसा सहित राज्य के कई हिस्सों में व्यापक असर देखने को मिला। गुरुवार, 15 अक्टूबर को बुलाए गए इस बंद के चलते सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। मानसा में बंद का व्यापक असर दिखा, जहां मानसा-सिरसा रोड पर प्रदर्शनकारी जमा हुए और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो भी सुरक्षा में मुस्तैद रहे। राज्य के अन्य हिस्सों से भी बंद को समर्थन मिलने की सूचनाएं हैं, जिसके मद्देनजर अमृतसर जैसे शहरों में भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था।

पुलिस उपायुक्त जसकरण सिंह तेजा ने बताया कि शांति व्यवस्था बनी हुई है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उन्होंने साफ किया कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा।

भारत का आसियान को बड़ा रक्षा प्रस्ताव

नई दिल्ली। भारत ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर अपनी एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़कर आसियान देशों को महत्वपूर्ण रक्षा प्रस्ताव दिया है। आसियान-इंडिया डिफेंस थिंक टैंक फोरम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन पार्टनर देशों को न सिर्फ स्वदेशी सैन्य उपकरण, जैसे ड्रोन, रडार और चॉपर उपलब्ध कराने की पेशकश की, बल्कि उनके साथ मिलकर इन उपकरणों के सह-उत्पादन और रख-रखाव का प्रस्ताव रखा है। यह कदम दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा भू-राजनीतिक संदेश देगा।

फेल हुआ ट्रंप का एनर्जी सीजफायर

कीव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 11 अक्टूबर, 2026 को सोशल मीडिया पर घोषित एनर्जी सीजफायर पहल पूरी तरह से विफल हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि रूस और यूक्रेन दोनों ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने को राजी हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर कर स्पष्ट किया कि रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला जारी रहेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि ट्रंप की घोषणा के बाद कीव ने दो-तीन दिनों के लिए रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोक थे, लेकिन इस दौरान रूस ने यूक्रेन के बिजलीघरों, गैस सुविधाओं और ऊर्जा ग्रिड पर अपने हमले जारी रखे।

1 नवंबर से बदलेंगे कॉलर आईडी के नियम

नई दिल्ली। मोबाइल फोन पर अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन की परिभाषा में संशोधन किया है। नया नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत कॉल करने वाले की पहचान में टेलीफोन नंबर के साथ टेलीकॉम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज ग्राहक का नाम भी शामिल होगा।

दूरसंचार विभाग ने 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि कॉलर की पहचान अब केवल फोन नंबर तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें ग्राहक के रिकॉर्ड में दर्ज नाम और सरकार की ओर से निर्धारित अन्य पहचान संबंधी जानकारी भी शामिल हो सकती है। यह संशोधन यूनिफाइड लाइसेंस के तहत आने वाली सभी संबंधित टेलीकॉम कंपनियों पर लागू होगा। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हर परिस्थिति में मोबाइल स्क्रीन पर नाम किस तरह दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग के अनुसार, संशोधित परिभाषा यूनिफाइड लाइसेंस समझौते का हिस्सा होगी। समझौते की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कदम का उद्देश्य कॉल करने वाले की पहचान से जुड़ी जानकारी के दायरे को स्पष्ट करना है।

नए नियम से कॉल करने वाले की पहचान समझने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, विभाग के आदेश में स्पैम कॉल या ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए किसी अलग व्यवस्था की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नए नियम से सभी फर्जी कॉल बंद हो जाएंगी। कॉलर की पहचान से जुड़ी जानकारी बढ़ने के बावजूद ठगी करने वाले अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अनजान कॉल पर निजी जानकारी, बैंक विवरण या ओटीपी साझा करने से बचना चाहिए।

अंकिता मामले में विनेश फोगाट हुई भावुक

नई दिल्ली। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश में महिलाओं की सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में होने वाली देरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को टैग करते हुए अपील की कि वे एक महिला होने के नाते देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों पर आत्ममंथन करें। विनेश की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब अंकिता के माता-पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने और मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल किया है, आखिर कब तक बेटियों को खोने वाले परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकते रहेंगे और सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते रहेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा, ह्यराष्ट्रपति जी, आप तो खुद एक महिला हैं, कभी अपने आप से दिल पे हाथ रखकर पूछिए कि देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए अभी तक क्या किया।

स्मृति ईरानी मध्यप्रदेश से जा सकती हैं राज्यसभा में

भोपाल। एल. मुरुगन के केंद्रीय मंत्री पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मध्यप्रदेश से राज्यसभा जाने की इच्छा रखने वाले नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस बीच भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा भेजने की संभावना को लेकर भी चचाएं हो सकती हैं।

पार्टी के रणनीतिक समीकरणों में उन्हें राज्यसभा भेजने के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दिए जाने का विकल्प भी शामिल हो सकता है। हाल ही में उत्तरप्रदेश की राज्यसभा सीटों को लेकर हुई राजनीतिक चचाओं के दौरान भी स्मृति ईरानी का नाम सामने आया था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्मृति ईरानी को मप्र से राज्यसभा भेजा जा सकता है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश की रिक्त सीट पर किसी स्थानीय नेता को प्राथमिकता देता है या राष्ट्रीय स्तर के किसी चेहरे को मौका देता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। मुरुगन के इस्तीफे से मध्यप्रदेश के कोटे से एक केन्द्रीय मंत्री कम हो जाएगा। जिसकी भरपाई अगले केन्द्रीय मंत्रीमण्डल विस्तार में की जा सकती है। जिसमें मध्यप्रदेश के किसी वरिष्ठ सांसद को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में जगह मिल सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार कर सकते हैं। भाजपा के सामने खाली हुई सीट पर किसी वरिष्ठ स्थानीय नेता को अवसर देने का विकल्प है। इससे प्रदेश संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वहीं, पार्टी किसी राष्ट्रीय नेता को मध्यप्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजकर उसे केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे सकती है। स्मृति ईरानी का नाम इसी संभावित राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में चर्चा में आ सकता है। हालांकि, भाजपा नेतृत्व की ओर से उनके नाम को लेकर कोई संकेत नहीं दिया गया है। ऐसे में फिलहाल इसे संभावित राजनीतिक चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

एक ही छत के नीचे स्कूल और कोचिंग चलाए जाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आजमगढ़ में एक ही छत के नीचे स्कूल और कोचिंग केंद्र चलाए जाने की जांच का निर्देश देते हुए कहा है कि कहीं ये संस्थान कोई ऐसा रैकेट तो नहीं चला रहे जिसमें विद्यार्थियों को उनकी जानकारी के बगैर एक ह्लडमी स्कूलह्व में दाखिल दिखाया जा रहा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने योगी सरकार को उस स्कूल के प्रबंधन की जांच करने और शाहाना इंटरनेशनल स्कूल, जौनपुर के साथ उनके कथित संबंध पर एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है। इसी स्कूल में याचिकाकर्ता अबु हुजैफा को सीबीएसई प्रणाली के तहत कक्षा 11 का विद्यार्थी दिखाया गया है, जबकि उसने इस स्कूल में दाखिला लेने की बात से इनकार किया है।

कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत हलफनामा के साथ जांच रिपोर्ट 2 नवंबर, 2026 तक अवश्य दाखिल करें। उस संस्थान के प्रधानाचार्य और प्रबंधक को भी अगली तिथि को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट अबु हुजैफा द्वारा योगी सरकार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

राजा वड़िंग जुझारू नेता आने वाले विधानसभा चुनाव में वह अहम भूमिका निभाएंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को जुझारू नेता बताते हुए कहा कि अगले साल की शुरूआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह अहम भूमिका निभाएंगे। पायलट ने एक इंटरव्यू में वड़िंग को बेहद ऊर्जावान और मेहनती युवा नेता बताया और कहा कि उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने में अहम योगदान दिया। पायलट के प्रदेश प्रभारी का दायित्व संभालने के कुछ दिनों बाद ही वड़िंग को हटाकर परगट सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने कहा कि वड़िंग ने संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन कई बार संगठन में बदलाव जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजा वड़िंग को 20 साल से जानता हूं। वह बेहद ऊर्जावान और मेहनती युवा नेता हैं। जब हमारे पास केवल 15-16 विधायक थे और परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण थीं, तब उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने में मदद की। चार साल से ज्यादा समय तक उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। पार्टी आलाकमान के फैसले के बाद वड़िंग ने दो अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और पूर्व ओलंपियन परगट सिंह ने उनकी जगह ली थी। उस समय वड़िंग ने पद छोड़ने के लिए परोक्ष रूप से पायलट को जिम्मेदार ठहराया था।

उन्होंने कहा कि वड़िंग ने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वह बहुत अहम भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने युवाओं के लिए काफी काम किया है और उन्हें आम आदमी पार्टी के खिलाफ आगे आकर संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन चुनाव के समय कई पहलुओं पर विचार किया जाता है और नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नए अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया। पायलट ने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं है कि निवर्तमान अध्यक्ष के पास कम काम होगा या चुनावी संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम हो जाएगी। उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और पंजाब में युवाओं को यह संदेश दे सकते हैं कि स्वास्थ्य, खेल और फिटनेस, नशे और भीड़ की हिंसा में शामिल होने से कहीं बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि परगट तीन बार के विधायक भी हैं और पार्टी ने मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें प्रदेश संगठन का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त माना है।

प्रदेश नेतृत्व को लेकर कई सप्ताह तक चली अंदरूनी खींचतान को कांग्रेस के चुनाव अभियान के लिए चुनौती माना जा रहा है। पायलट ने कहा कि पंजाब में बीजेपी कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती नहीं है और मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा।

तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामलाः ईडी ने 130 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

हैदराबाद। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को कथित तौर पर मिलावटी घी की आपूर्ति करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत करीब 130 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले में अटैच, जब्त या फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 132.5 करोड़ रुपये हो गया है।

ईडी के अनुसार, अटैच संपत्तियां भोल बाबा ऑर्गेनिक डेयरीमिल्क प्राइवेट लिमिटेड, श्री वैष्णवी डेयरी स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके प्रमोटरों और संबंधित लोगों की हैं।

जांच एजेंसी का आरोप है कि भोल बाबा ने सीधे और कथित फ्रंट डेयरियों के माध्यम से टीटीडी को 234.5 करोड़ रुपये मूल्य का मिलावटी घी सप्लाई किया। आरोप है कि घी बनाने के लिए रिफाइंड पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और पामोलीन में विभिन्न रसायन मिलाए गए। उत्पादों को खाद्य तेल के रूप में दर्ज कर उनकी वास्तविक प्रकृति छिपाने की कोशिश की गई। ईडी के मुताबिक, फर्जी दूध और घी की खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड तैयार किए गए। बैंक के जरिए किए गए कथित फर्जी भुगतानों की रकम हवाला चैनलों से नकद लौटाई जाती थी। इस धन का इस्तेमाल कमीशन देने और अन्य लेनदेन में किए जाने का आरोप है।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- न्यायपालिका पर दबाव नहीं चलेगा

राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई, चुनाव आयोग को नोटिस

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम सुनवाई की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में एसआईआर प्रक्रिया और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है।

सीजेआई बोले- हम हाथीदांत की मीनार में बैठकर काम नहीं कर रहे

सुनवाई के दौरान एसआईआर के कथित अनियमितताओं के विरोध में विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का मुद्दा भी उठा। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी न्यायपालिका को दबाव में नहीं डाल सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ह्यहाथीदांत की मीनार में बैठकर काम नहीं कर रही हैह्व और बाहर हो रही घटनाओं तथा दिए जा रहे बयानों से अनजान नहीं है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने राजनीतिक जुलूस और घटनाक्रम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि करीब 200 वकीलों ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के कथित प्रयासों के खिलाफ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे प्रयासों से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने 13 याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में संबंधित याचिकाकर्ता से उसके आचरण के बारे में सवाल किया जाएगा। हालांकि, अदालत की इस टिप्पणी के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं किया गया।

एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची पर उठाए सवाल

विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगते हुए इस मामले में आगे सुनवाई का रास्ता खोला है। सुनवाई के दौरान असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य नेताओं की ओर से दाखिल निर्वाचन आयोग से संबंधित याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किए गए। अदालत ने समान राहत मांगने वाली याचिकाओं को एक साथ रखने का निर्देश दिया। अब मामले में चुनाव आयोग के जवाब और अगली सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों पर नजर रहेगी।

कई विपक्षी नेताओं ने दाखिल की याचिका

याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले और शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत सहित अन्य विपक्षी नेता शामिल हैं। याचिका 12 अक्टूबर को दाखिल की गई थी और प्रक्रियात्मक कमियां दूर होने के बाद 13 अक्टूबर को इसे पंजीकृत किया गया।

संपादकीय

हदों के पार महंगाई

खुदरा महंगाई ने बीते 23 माह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत सरकार के ही सांख्यिकी मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं कि सितंबर, 2026 में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी रही। यह अक्तूबर, 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है। तब महंगाई दर 6.2 फीसदी थी। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि आने वाले महीनों में भी महंगाई बढ़ेगी। अक्तूबर-दिसंबर की औसत महंगाई दर 6 फीसदी या उससे अधिक भी हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने महंगाई दर की सीमा वैसे तो 4 फीसदी तय कर रखी है, लेकिन उसे 6 फीसदी तक सामान्य मान कर तमाम आकलन और विश्लेषण किए जाते हैं। लगातार चौथे माह उस लक्ष्मण-रेखा को लांघा गया है, क्योंकि खाद्य महंगाई दर और शहरी-ग्रामीण इलाकों में महंगाई की स्थितियां भिन्न और अधिक हैं। खाद्य महंगाई दर सितंबर में बढ़ कर 7.74 फीसदी तक पहुंच गई। गांवों में खुदरा महंगाई दर 5.24 फीसदी से बढ़ कर 6.08 फीसदी हो गई। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 8.06 फीसदी और शहरों में 7.18 फीसदी दर्ज की गई है। ये तमाम आंकड़े रिजर्व बैंक की तय हदों के पार हैं, लिहाजा साफ है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गैर-सरकारी और पेशेवर संगठनों, संस्थानों, एजेंसियों के आंकड़े भिन्न और अपेक्षाकृत अधिक हैं। आम आदमी महंगाई के इन प्रतिशत वाले आंकड़ों का अर्थशास्त्र नहीं जानता। उसके लिए महंगाई वहीं से शुरू होती है, जब आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, नींबू, अदरक और हरी मिर्च सरीखी रोजमर्रा की सब्जियां महंगी मिलने लगती हैं। इस बाजार और भाव पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सब्जी मंडी के व्यापारी आपस में मिल कर कीमतें तय कर लेते हैं, वहीं से खुदरा बाजार भी महंगा हो जाता है। गली-मुहल्ले के छोटे कारोबारी और रेहड़ीवाले भी उसी अनुपात में दाम बढ़ा देते हैं। तर्क दिया जाता है कि ऊपर से ही भाव बढ़ गए हैं। हम क्या कर सकते हैं जी? यदि प्याज करीब 108 फीसदी और लहसुन 55 फीसदी महंगा और आलू 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो यह किस अर्थशास्त्र के आधार पर तय किया जाता है, कमोबेश आम आदमी नहीं जानता।

सरकार के अधीन कई संस्थान, प्राधिकरण, संघ आदि ऐसे हैं, जो इन सब्जियों की तुरंत आपूर्ति कर आम उपभोक्ता को राहत दे सकते हैं और मुद्रास्फीति को तय हदों के भीतर रख सकते हैं। वे दाम बढ़ने की स्थितियों में ऐसा कुछ करते भी हैं, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे समान ही होता है। यह देश बहुत विराट, विशाल और विविध है, लिहाजा ऐसे संकटों को संबोधित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर सरकार किसलिए चुनी जाती है? इन संस्थानों की कार्य-प्रणाली और सम्यक सक्रियता भी सवालिया रही हैं। नतीजा यह है कि महंगाई हमारे लिए एक शाश्वत, चिरंतन और स्थायी समस्या बन कर रह गई है। बहरहाल महंगाई दर सिर्फ सब्जियों और खाद्य पदार्थों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा खुदरा महंगाई दर के कारण रेस्तरां-होटल 9.36 फीसदी, परिवहन 5 फीसदी से ज्यादा, शिक्षा सेवाएं और कपड़े-जूते करीब 4 फीसदी प्रति और घरेलू उपकरण 3.26 फीसदी महंगे हो गए हैं। जाहिर है कि औसत घर और परिवार का बजट बिखर और बिगड़ जाता है। औसत नौकरी, दिहाड़ीदार मजदूर, खेतिहर मजदूर, रिक्शेवाला, माल ढोने वाला अर्थात देश का गरीब तबका कहां से अतिरिक्त बजट का जुगाड़ करेगा, ताकि महंगाई से लड़ सके? कोई रास्ता नहीं, कोई समाधान नहीं! सरकार और मंत्रीगण जुमले उछालने में व्यस्त हैं कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द ही बन जाएगा। सरकारी किस्म के प्रवक्ता कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दौरान 12-14 फीसदी मुद्रास्फीति से तुलना करने लगते हैं। यथार्थ तो यह है कि महंगाई बढ़ रही है, जो आम आदमी के लिए असहनीय है। रिजर्व बैंक को साढ़े तीन साल के बाद, अंततः, रेपो रेट 0.25 फीसदी बढ़ाने पड़े। अब यह ब्याज दर 5.50 फीसदी हो गई है। नतीजतन आम उपभोक्ता के लिए गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, मोबाइल ऋण आदि सभी की मासिक किस्तें बढ़ जाएंगी। इस महंगाई का बोझ कैसे उठाया जाए। संभव है कि बाजार में ऋण की मांग ही कम हो जाए! मांग कम होगी, तो बाजार प्रभावित होगा। बेशक सत्ताधीश चिंतन जरूर करते होंगे! केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महंगाई के संबंध में किए गए वादे को निभाना चाहिए। महंगाई कम करके ही गरीबों का कल्याण होगा।

मोदी मंत्रिमंडल के अहम फैसले : रेलकर्मियों को दीपावली की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले देश की आर्थिक दिशा, प्रशासनिक प्राथमिकताओं और जनकल्याण के प्रति सरकार की सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। 14 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में भारतीय रेल के 11.40 लाख से अधिक पात्र कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता-संबद्ध बोनस को मंजूरी देना और आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना विशेष महत्व रखता है। एक ओर दीपावली से पहले रेलकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने का निर्णय है, तो दूसरी ओर बैंकिंग क्षेत्र में बड़े निवेश और प्रबंधन संबंधी बदलाव का रास्ता खुलता दिखाई देता है। इन दोनों फैसलों के केंद्र में अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखें तो इनका संबंध आर्थिक गतिविधियों, संस्थागत कार्यकुशलता और विकास की निरंतरता से जुड़ता है।रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस की सौगात भारतीय रेल केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक जीवनरेखा है।प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने से लेकर उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई तक, रेलवे की भूमिका देश के विकास में महत्वपूर्ण है। इस विशाल व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में लाखों कर्मचारियों का योगदान रहता है।रेलगाड़ियों का सुरक्षित परिचालन, पटरियों का रखरखाव, तकनीकी व्यवस्थाओं का संचालन, स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता और मालगाड़ियों की आवाजाही जैसे कार्यों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन के आधार पर लगभग 11,40,770 पात्र रेलकर्मियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता- संबद्ध बोनस को मंजूरी दी है। इस पर कुल 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये तक बोनस मिलेगा। यह निर्णय त्योहार के मौसम में कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ उनके परिश्रम और योगदान को सम्मान देने का भी संदेश देता है।

वर्तमान समय में परिवारों के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और दैनिक जरूरतों से जुड़े अनेक खर्च हैं।ऐसे में दीपावली से पहले मिलने वाली अतिरिक्त राशि से रेलकर्मियों को अपने घरेलू बजट को व्यवस्थित करने और त्योहार की तैयारियां करने में सहायता मिलेगी। लाखों परिवारों तक पहुंचने वाली यह राशि बाजार में मांग बढ़ाने में भी योगदान दे सकती है। त्योहारों के दौरान खरीदारी बढ़ने से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और विभिन्न सेवाओं से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना रहती है उत्पादकता- संबद्ध बोनस का महत्व केवल आर्थिक भुगतान तक सीमित नहीं है। यह कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करने और कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने का माध्यम भी है। रेलवे में सुरक्षा और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। आधुनिक तकनीक, नई रेल लाइनों, विद्युतीकरण और उन्नत परिचालन प्रणालियों के साथ कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अनुभव और अनुशासन

भी उतना ही आवश्यक है।पिछले वर्षों में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी व्यापक होगा, जब कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां, आवश्यक प्रशिक्षण और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। बोनस जैसे निर्णय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।इसके साथ ही रेलवे की कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार और यात्रियों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना भी आवश्यक है।

मंत्रिमंडल की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश से संबंधित है।सरकार ने फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहायक कंपनी को बैंक में रणनीतिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए स्वीकृति दी है। इस सौदे के तहत केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 52,878.08 करोड़ रुपये में बेची जाएगी। घोषित सौदे के अनुसार, शेयर का मूल्य 81 रुपये निर्धारित किया गया है, जो स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर तय 75.99 रुपये के संदर्भ मूल्य से अधिक है। लेनदेन पूरा होने के बाद सरकार और एलआईसी की संयुक्त हिस्सेदारी 34 प्रतिशत रहने की जानकारी दी गई है।यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की भूमिका, निजी निवेश और वित्तीय संस्थानों की कार्यकुशलता से जुड़ी व्यापक बहस को फिर सामने लाता है। रणनीतिक विनिवेश का उद्देश्य केवल सरकारी हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं, बल्कि किसी संस्थान को पूंजी, प्रबंधन क्षमता और प्रतिस्पर्धा के लिहाज से अधिक सक्षम बनाने की संभावनाओं से भी जुड़ा होता है।बदलते बैंकिंग परिदृश्य में डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा, ग्राहकों को त्वरित सेवाएं, ऋण वितरण और जोखिम प्रबंधन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बैंक के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना, ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना आवश्यक है।यदि रणनीतिक निवेश से इन क्षेत्रों में सुधार होता है, तो इसका लाभ बैंक की दीर्घकालिक स्थिति को मजबूत करने में मिल सकता है।हालांकि,इतने बड़े सौदे की सफलता का आकलन केवल सरकार को प्राप्त होने वाली राशि से नहीं किया जाना चाहिए। बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा, कर्मचारियों के हित, ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता भी महत्वपूर्ण हैं।नियामकीय शर्तों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सौदे को पूरा करना आवश्यक होगा। यह भी देखना होगा कि स्वामित्व और प्रबंधन में बदलाव के बाद बैंक अपनी सेवाओं को किस प्रकार बेहतर बनाता है।कर्मचारी कल्याण और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन रेलवे बोनस और आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को एक साथ देखने पर सरकार की दो अलग-अलग नीतिगत प्राथमिकताएं सामने आती हैं। रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय उनके योगदान को सम्मानित करने और त्योहार के अवसर पर आर्थिक सहायता पहुंचाने से संबंधित है। वहीं आईडीबीआई बैंक के विनिवेश का उद्देश्य संस्थागत ढांचे और प्रबंधन में बदलाव के माध्यम से बैंक की क्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना है।भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था में विकास की गति बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश, उद्योगों का विस्तार, रोजगार के अवसर और मजबूत वित्तीय संस्थान आवश्यक हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के हितों और आम नागरिकों की जरूरतों की अनदेखी नहीं की जा सकती। आर्थिक सुधार तभी सार्थक होंगे, जब उनका लाभ व्यापक समाज तक पहुंचे और संस्थानों के प्रति जनता का विश्वास बना रहे।

रेलवे में कर्मचारियों की कार्यकुशलता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। दूसरी ओर, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश और प्रबंधन सुधार से वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ने की संभावना है। दोनों ही मामलों में घोषणाओं से आगे बढ़कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण,निवेश को प्रोत्साहन और आर्थिक सुधारों को विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा गया है। इन प्रयासों का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उनसे रोजगार, उत्पादकता, सेवाओं की गुणवत्ता और आम नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है।अंततः 14 अक्टूबर की मंत्रिमंडलीय बैठक के ये दोनों फैसले आर्थिक विकास के दो महत्वपूर्ण पक्षों को सामने रखते हैं।रेलकर्मियों के लिए बोनस का निर्णय श्रम और सेवा के सम्मान का संदेश देता है, जबकि आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश वित्तीय क्षेत्र में बदलाव की दिशा को रेखांकित करता है। देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि आर्थिक सुधारों के साथ जनहित सुरक्षित रहे, कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही बनी रहे। विकास की यही संतुलित दृष्टि भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

लेखक-विनोद सिंह तकियावाला, (लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)

राहुल गांधी के पक्ष में आया विपक्ष

भारत की राजनीति बड़ी तेजी के साथ बदलती हुई दिख रही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच में राहुल गांधी की स्वीकार्यता दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद होने का लाभ भाजपा को मिलता रहा है। भाजपा की रणनीति रहती थी, विपक्ष में लगातार मतभेद बने रहें और वोटों का बंटवारा होता रहे, ताकि इसका फायदा भाजपा को मिले। अब स्थितियां बड़ी तेजी के साथ बदलती हुई दिख रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली तथा चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया का केंद्रीकरण कर के कंप्यूटर के माध्यम से चुनाव परिणाम और मतदाता सूची को प्रभावित किया जा रहा है। उसको लेकर अब सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अस्तित्व की चिंता में जुट गए हैं। यदि समय रहते क्षेत्रीय दलों ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस डर और भय के कारण ममता बनर्जी जैसी सशक्त महिला राजनीतिज्ञ इंडिया गठबंधन की ओर बिना शर्त आकर्षित हुई हैं। उन्हें भी समझ आ गया है, कम्युनिस्ट पार्टी से तो कभी भी लड़ा जा सकता है। कांग्रेस के समर्थन बिना पश्चिम बंगाल में अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, आज भी कांग्रेस पार्टी का गांव-गांव में अस्तित्व बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जब सबसे ज्यादा कमजोर था, कोई मजबूत नेता कांग्रेस में नहीं था। उस समय भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 300 से अधिक सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर वोट पाने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस पार्टी चुनौती दे सकती है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है। पिछले 12 वर्षों मे भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले रखा था। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है, पप्पू हैं, इसके पीछे एक ही रणनीति थी। जब भी भाजपा को चुनौती मिलेगी, तो वह कांग्रेस पार्टी से मिलेगी। जब तक राहुल गांधी का कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में वजूद रहेगा,

तब तक भाजपा को कोई खतरा नहीं होगा। स्थिति इस तरह से बदलेगी, इसका अंदाजा भाजपा के नेताओं को नहीं था। देखते ही देखते राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की चुनौती मिलेगी, यह तो सपने में भी भाजपा ने नहीं सोचा था। इंडिया गठबंधन इस तरह से मजबूत होगा, इसकी कल्पना भी भाजपा नेताओं को नहीं थी। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर के इतने बड़े दुष्परिणाम सामने आएंगे, इसकी भाजपा ने कल्पना में नहीं की थी। न्यायपालिका का जो समर्थन सरकार के पक्ष में था अब वह भी कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की स्थितियां महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तेजी से बदल रही हैं, उसने सरकार और भाजपा की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे 2012 से 2014 के बीच में कांग्रेस और यूपीए गठबंधन के नेता घिरे थे।

राहुल गांधी ने जिस साहस के साथ प्रधानमंत्री का मुकाबला किया है। उसके कारण राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ आम जनता के बीच में भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, जिनकी पहचान अब उत्तर-दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं में एक राष्ट्रीय और सशक्त नेता के रूप में बनी है। युवाओं के बीच में भी उनकी लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ी है। विभिन्न राज्यों में छात्रों की गूंज के नाम से जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, उससे उनकी युवा वर्ग के बीच में बड़ी तेजी के साथ पेठ बड़ी है। जो सरकार के लिए अब चुनौती बनकर सामने आ गई है। रही-सही कसर काकरौंच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन ने पूरी कर दी है। डर और भय का जो माहौल बना हुआ था, लोग विरोध करने से डरते थे, अब वह मुखर होकर सड़कों पर आ रहे हैं। जेन जेड और जेन अल्फा के युवाओं ने देश की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। न्याय पालिका की विश्वसनीयता भी आम जनता के बीच में वह नहीं है, जो पहले कभी होती थी। न्यायपालिका से जो संरक्षण अभी तक भाजपा और सरकार को मिलता रहा है, अब वह भी मिलना संभव नहीं दिख रहा है। विपक्ष का एकजुट होना तथा राहुल गांधी की लोकप्रियता सारे देश में समान रूप से होना जहां भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। वहीं क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति में जो बदलाव देखने को मिल रहे है वहीं क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की ओर आकर्षित कर रहा है। उसके बारे में अब लोग यह कहने लगे हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाजपा की तुलना में राहुल गांधी और कांगेस का ग्राफ बढ़ रहा है।

लेखक- सनत जैन

मेडीकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नुकसानदेह

पिछले कुछ सालों से देश भर में नये मेडीकल कॉलेज खोलने की होड़ मची हुई है और कोई भी राज्य सरकार पीछे नहीं छूटना चाहती इसलिए जब तब नये मेडीकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं अखबारों की सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने भी 12 और मेडीकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार की यही कहानी है और नतीजा यह कि 2014 में 387 से बढ़कर 2026 में मेडीकल कॉलेजों की संख्या 858 हो चुकी है।

इसी अवधि में एमबीबीएस की सीटें 51 हजार से बढ़कर एक लाख 1 लाख 40 हजार तथा पीजी की सीटें 31 हजार से बढ़कर 86 हजार हो चुकी हैं। इस बीच महाराष्ट्र आईएमए के प्रदेश सहसचिव डॉ अनुपम ताकलकर का बयान गौरतलब है कि इस बढ़ोत्तरी पर विराम देने की जरूरत है क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी आशंका है।

वाकई इस मामले पर पुनर्विचार एवं गहन मंथन की आवश्यकता है। जनता में लोकप्रियता हासिल करने के लिये राजनेता इस तथाकथित विकास का आश्वासन दे रहे हैं परन्तु वास्तव में यह औचित्यहीन कदम स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर डालने वाला है। दरअसल किसी अन्य शिक्षा संस्थान की तुलना में मेडीकल शिक्षा एकदम अलग है। उदाहरण के लिये एक बढ़िया तकनीकी संस्थान खोलने में जमीन, भवन, हॉस्टल, प्रयोगशाला, उपकरण तथा शिक्षकों की व्यवस्था करना ही पर्याप्त होता है। लेकिन मेडीकल कॉलेज में इन सबकी व्यवस्था के अलावा एक और अनिवार्य जरूरत होती है कि वहां बड़ी संख्या में मरीज भी आयें। तकनीकी शिक्षा तो किसी उन्नत प्रयोगशाला में ही प्राप्त की जा सकती है जबकि मेडीकल शिक्षा के लिये मरीज एक अनिवार्य फैक्टर है क्योंकि यह पढ़ाई ऐसी है जिसमें छात्रों से मरीज देखने एवं रोग का निदान तथा उपचार करने का ही कार्य करवाया जाता है। यानी छात्र प्रशिक्षण के साथ ही उपचार का अनिवार्य अनुभव हासिल करते हैं।

यद्यपि मेडीकल कॉलेज खोलने के लिये निर्धारित न्यूनतम जमीन की शर्त अब हटा दी गई है लेकिन फिर भी इसके लिये काफी ज्यादा जमीन की जरूरत होती है जो आम तौर पर शहरों के बीच उपलब्ध नहीं होती। इसलिए नए मेडीकल कॉलेज शहर से दूर स्थानों पर बनाए जाते हैं। सर्वविदित है कि ऐसे बहुत से नये मेडीकल कॉलेजों में मरीजों का पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिये कहीं कहीं मुफ्त ऑटो या मुफ्त बस सेवा की व्यवस्था की जाती है। फिर भी वांछित संख्या में मरीज नहीं पहुंच पाते। उस पर शिक्षकों का अभाव दूसरी बड़ी समस्या है। मेडीकल शिक्षा की नियामक संस्था एनएमसी के निरीक्षण दौरे के समय शिक्षकों को उपस्थित अवश्य दिखा दिया जाता है लेकिन ये सिर्फ खानापूरी के लिये आते हैं। हालत यह है कि अधिकांश मेडीकल कॉलेज इसी तरह की घोस्ट फैकल्टी (छद्म शिक्षक) से चल रहे हैं। वही हाल पीजी शिक्षण का भी है। इस वजह से बहुत से ऐसे डॉक्टर तैयार किये जा रहे हैं जिनका क्लीनिकल ज्ञान अधूरा है फिर भी वे पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना ही मरीजों का उपचार करने के लिये अधिकृत हैं।

इस के साथ ही एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू नजरअंदाज किया जा रहा है। वास्तव में सरकार जितना पैसा इन मेडीकल कॉलेजों के खोलने पर खर्च करना चाहती है उस से कम में सारे जिला अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर खर्च करके उन सबका विकास और उन्नयन किया जा सकता है। आखिर तो जनता को सिर्फ इलाज चाहिये। खूबसूरत बिल्डिंग और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉलेजों में यदि योग्य डॉक्टर नहीं होंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। इससे बेहतर होगा कि सरकार जिला अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैसा खर्च करे।

वैसे भी देश में वास्तविक स्थितियों को नजरअंदाज करके कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता देने की परम्परा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य योजनाओं का भी यही हाल है। उचित गाइडलाइंस के अभाव में आयुष्मान योजना भी दम तोड़ रही है। सरकार प्राइवेट अस्पतालों पर दोष मढ़ती है और अस्पताल सालों से लम्बित पड़े करोड़ों के बाकी भुगतान को लेकर लामबंद हो रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र बिल्कुल खस्ताहाल हैं जहां न दवाएं हैं और न ही डॉक्टर। जिला अस्पतालों में भी डॉक्टर और स्टॉफ के सैकड़ों पद खाली हैं जिससे वे मरीजों का दबाव झेलने में असमर्थ हैं। लेकिन कागजों पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जारी है जिसमें नए नए मेडीकल कॉलेज खोलना एक शिगूफे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे ये वास्तविकता आम जनता को भी समझ आ रही है। अभी जारी 2026-27 के सत्र की काउंसलिंग में नीट यूजी की लगभग 6000 सीटें खाली हैं। प्राइवेट मेडीकल कॉलेजों की करोड़ों की फीस और लगातार गिरती साख के चलते हो सकता है कि ये सीटें पूरी न भर पायें। पिछले साल पीजी की करीब 20000 सीटें खाली रह गई थीं जिसके बाद सरकार ने कट ऑफ समाप्त कर दिया था। उसके बाद हजारों ऐसे छात्र भी पीजी में प्रवेश के पात्र हो गये थे जिन्हें माइनस में मार्क्स मिले थे। ऐसी परिस्थिति में और अधिक मेडीकल कॉलेज खोल कर अयोग्य डॉक्टर तैयार करना सिर्फ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जा सकता है। इसलिए अंधाधुंध मेडीकल कॉलेज खोलने से बेहतर ये होगा कि उसी धनराशि से सभी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल विकसित और उन्नत किये जायें जिससे आसपास के ग्रामीण मरीजों को सही उपचार के लिये कहीं दूर न जाना पड़े। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तभी उचित है जब उसमें विधिवत शिक्षा की पूरी व्यवस्था उपलब्ध हो सके। मरीजों की उचित संख्या के अभाव और नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता के चलते ये नए मेडीकल कॉलेज सिर्फ शोपीस का काम करेंगे। ऐसी अधूरी शिक्षा और अपूर्ण प्रशिक्षण के बाद जो डॉक्टर निकलेंगे वे रोगों के निदान और उपचार में भली भांति प्रशिक्षित एवं पारंगत नहीं होंगे। सरकारों को चाहिये कि वे संख्या के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान दें। वोट हासिल करने के लिये नए नए मेडीकल कॉलेज खोलते जाना वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नुकसानदेह ही साबित होगा।

लेखक - डॉ. योगेन्द्र श्रीवास्तव

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आलेख

एसआईआर पर अमित शाह का जवाब क्यों बढ़ा रहा है वोट चोरी के सवाल?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को वापस लेने, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और वोट चोरी के आरोपों की जांच कराने की मांग को लेकर देश में इन दिनों एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो गया है। यह आंदोलन अब किसी एक दल का मुद्दा नहीं रह गया है। इसमें इंडिया ब्लॉक के नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, छात्र संगठन और आम नागरिक शामिल हो रहे हैं। सोमवार शाम राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह बड़ी संख्या में लोग सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किए, उसने साफ संदेश दिया कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अब दबाए नहीं जा सकते। इस मार्च में कथित तौर पर दो से ढाई लाख लोग जुटे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़क पर उतरना इस बात का प्रमाण है कि चुनाव प्रणाली पर भरोसा बहाल करने का मुद्दा जनता तक पहुंच चुका है।

एसआईआर के खिलाफ आवाजें पहले से उठ रही थीं, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद यह आंदोलन अधिक संगठित रूप लेने लगा। पहले कॉकरोच जनता पार्टी, सिविल सोसायटी और कांग्रेस अलग-अलग मोर्चों से इस मुद्दे पर बोल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ किया कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सभी एक साथ हैं, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य है कि हर वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची में बना रहे, कोई नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो और चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता व निष्पक्षता साबित करे। राजनीतिक दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, रणनीतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन संविधान, मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा जैसे मुद्दों पर एकजुटता जरूरी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने इस आंदोलन से जुड़े लोगों को चाय पर बुलाया और फिर सबके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे स्पष्ट हुआ कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या दल की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई है। राहुल गांधी ने बार-बार यही संदेश दिया कि चुनाव चोरी के खिलाफ लड़ाई में सब साथ हैं। इसके बाद बुधवार सुबह जब अभिजीत दिपके के साथी आशुतोष रांका और सौरव दास को जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के आरोप में तिहाड़ जेल भेजा गया, तब भी राहुल गांधी ने पोस्ट करके कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सब साथ हैं और जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना कोई अपराध नहीं है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रध्वज और संविधान के प्रति सम्मान को दमन का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

भाजपा इसी दिन की कल्पना से डरती थी जब राहुल गांधी को विपक्ष का सर्वमान्य नेता माना जाने लगे। इसीलिए उसने लगातार कोशिश की कि कांग्रेस और राहुल गांधी को अन्य विपक्षी दलों से अलग-थलग किया जाए। उन पर विभिन्न आरोप लगाए गए, उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता पर सवाल उठाए गए और उन्हें चुनाव चोरी के मुद्दे से अलग करने की कोशिश की गई। लेकिन अब यह रणनीति अपेक्षित असर नहीं दे रही है। जब चुनाव चोरी के खिलाफ आंदोलन में जनता भी जुड़ने लगी, तो भाजपा के लिए केवल छोटे नेताओं के बयान पर्याप्त नहीं रहे। 2 अक्टूबर के बाद कई भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनके तर्क जनता के सामने प्रभावी नहीं हो पाए।

अंततः गृहमंत्री अमित शाह को खुद मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर बयान दिया। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए, तो जवाब अमित शाह क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे अपने फैसलों की व्याख्या स्वयं करनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी है, तो उसे खुद सबूत, आंकड़े और तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। गृहमंत्री का जवाब देना इस धारणा को और मजबूत करता है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाने की स्थिति में सत्ताधारी पार्टी भी सीधे उसकी रक्षा में उतर आई है।

अमित शाह को कायदे से यह कहना चाहिए था कि वे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं और यदि आरोप गलत हैं तो ज्ञानेश कुमार की जगह किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति पर भी आपत्ति नहीं होगी। ऐसा करके वे यह साबित कर सकते थे कि भाजपा जो चुनाव जीत रही है, वह चुनाव आयोग की किसी गड़बड़ी से नहीं, बल्कि अपने दम पर जीत रही है। लेकिन इसके बजाय उन्होंने ऐसे बयान दिए, जिनसे सवाल और बढ़ गए। उन्होंने दावा किया कि 2029 में भी भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और कांग्रेस को बड़ी हार मिलेगी। लोकतंत्र में कोई भी नेता चुनाव से तीन साल पहले इतना निश्चित दावा नहीं कर सकता। जनता ही तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चुनाव से पहले ही परिणाम का ऐलान करना लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के खिलाफ जाता है।

एसआईआर पर सवाल उठाने वाले लोग पूछ रहे हैं कि बिना ठोस आधार के मतदाताओं के नाम काटे क्यों जा रहे हैं और अचानक नए नाम क्यों जोड़े जा रहे हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि किसी मतदान केंद्र पर मतदान समाप्त होने तक कितने वोट पड़े, इसका सही आंकड़ा तुरंत क्यों नहीं आ पाता। शाम तक अचानक वोट प्रतिशत बढ़ जाता है और दो-तीन दिन बाद उसमें और इजाफा हो जाता है। एक मतदान केंद्र पर कितने लोग वोट डालने आए, इसकी सही गिनती रखना इतना कठिन क्यों हो सकता है? ये सवाल गंभीर हैं क्योंकि लोकतंत्र की नींव भरोसे पर टिकी होती है। जब मतदाता को लगे कि उसके वोट की गिनती, उसकी सूची में उपस्थिति और उसकी भागीदारी पर सवाल हैं, तो चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर होता है।

इन सवालों का जवाब देने की बजाय अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। यह आरोप गंभीर है, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गंभीर है। क्या जिन करोड़ों लोगों को एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बाहर किया गया है, वे सभी घुसपैठिए हैं? यदि ऐसा है, तो गृहमंत्री के रूप में अमित शाह की जिम्मेदारी क्या है? देश की सीमाओं को लांघकर इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर घुस आए हैं, तो यह सरकार की बड़ी नाकामी है। ऐसी स्थिति में गृहमंत्री को जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने जवाबदेही की बजाय विपक्ष पर हमला बोला और कांग्रेस की राजनीतिक हालत पर टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन हर गली-कूचे और दूर-दराज के इलाकों में मौजूद है, जबकि कांग्रेस खेत-खलिहानों, नदी-पहाड़ों से गायब है। उन्होंने गुजरात, बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांग्रेस की हार का हवाला दिया। लेकिन एसआईआर पर उठे सवालों को कांग्रेस की हार से नहीं टाला जा सकता। चुनाव आयोग की प्रक्रिया, मतदाता सूची की सटीकता और वोटों की पारदर्शी गिनती किसी एक पार्टी की जीत-हार से जोड़कर नहीं देखी जा सकती। यदि किसी दल की कमजोर स्थिति है, तो भी उसके मतदाताओं का अधिकार बरकरार रहना चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट समान महत्व रखता है, चाहे वह किसी भी दल को वोट दे।

अमित शाह चाहें तो राहुल गांधी को अपने किसी मंच पर आमंत्रित करके आमने-सामने सवाल-जवाब कर सकते हैं। इससे उनके तर्क का वजन भी बढ़ेगा और जनता को स्पष्ट जानकारी भी मिलेगी। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग के नाम पर केवल चुनिंदा एजेंसियों के सामने तैयार बयान पढ़ना जनता के सवालों का जवाब नहीं है। जब नेता केवल अपने पक्ष की बात कहते हैं और विरोधी के सवालों का सीधा उत्तर नहीं देते, तो संदेह और गहरा जाता है। लोकतंत्र में संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही ही भरोसा बनाते हैं। इस बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने भी एसआईआर के दौरान एक बड़े कानूनी मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है। उनके अनुसार, यदि चुनाव से पहले संशोधित मतदाता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता, तो पहले प्रकाशित सूची का ही उपयोग होना चाहिए। फिर भी पश्चिम बंगाल में संशोधित सूची के आधार पर चुनाव कराए गए, जबकि लाखों योग्य मतदाता सूची से बाहर रह गए और उनकी अपीलें लंबित थीं। यही स्थिति बिहार में भी बताई जाती है। यदि यह सही है, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि मतदाताओं के मौलिक अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला है। अदालत से यह उम्मीद की जाती है कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे।

अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह का एसआईआर पर जवाब देना विपक्ष के चुनाव चोरी के आरोपों को और मजबूत कर गया है। जब चुनाव आयोग पर उठे सवालों का जवाब चुनाव आयोग की बजाय गृहमंत्री देते हैं, जब मतदाता सूची की समस्या को कांग्रेस की हार से जोड़ा जाता है और जब चुनाव से तीन साल पहले जीत का दावा किया जाता है, तो जनता के मन में सवाल और बढ़ते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची पारदर्शी हो, चुनाव आयोग स्वतंत्र रहे, हर वैध मतदाता का नाम सूची में रहे और हर वोट की गिनती भरोसे के साथ हो। यही असली लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है।

लेखक - सचिन कुमार गौतम

संक्षिप्त वार्ता

दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली के कई स्कूलों को बृहस्पतिवार को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद पुलिस टीमों को परिसरों में भेजा गया।

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मी स्कूलों में परिसरों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अबतक तक स्कूलों में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। आगे की जांच चल रही है।

सीलमपुर में 32 वर्षीय व्यक्ति की दुकान में गोली मार की हत्या

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बुधवार रात 32 वर्षीय व्यक्ति की उसकी दुकान में अज्ञात हमलावर ने गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान वसीम के रूप में हुई है जो न्यू सीलमपुर के ई-ब्लॉक कि झुग्गियों रहता था। अधिकारी के अनुसार, गली नंबर नौ में नाले के पास स्थित उसकी दुकान पर उसे गोली मारी गई। इसके बाद स्थानीय लोग वसीम को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह इलेक्ट्रिक सामान की मरम्मत का काम करता था। पुलिस ने बताया कि रात करीब नौ बजकर चार मिनट पर सीलमपुर थाने को जेपीसी अस्पताल से गोली लगने के बाद एक व्यक्ति को भर्ती कराए जाने की सूचना मिली।

न्यायाधीशों पर निजी हमलों की दिल्ली बार काउंसिल ने निंदा की, संयम बरतने की अपील की

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली बार काउंसिल ने न्यायाधीशों पर निजी हमलों की निंदा करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखा है और बार काउंसिल के सभी सदस्यों और जिम्मेदार नागरिकों से न्यायपालिका की आलोचना करते समय संयम बरतने की अपील की है।

बार काउंसिल ने 13 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि न्यायपालिका संवैधानिक लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है और कानून का शासन तभी कायम रह सकता है तथा फल-फूल सकता है, जब देश में एक स्वतंत्र और प्रभावी न्यायिक व्यवस्था हो। यह पत्र कांग्रेस की केरल इकाई की ओर से सोशल मीडिया पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत से इस्तीफे की मांग किए जाने के बाद उत्पन्न बड़े राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में आया है।

सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में किया डीजीएचएस का उद्घाटन

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। सीजेआई सूर्यकांत की ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य केंद्र (डीजीएचएस) के विस्तार खंड का उद्घाटन किया गया।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, ह्लदिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के सहयोग से यहां बार सदस्यों और हमारे स्टाफ के लिए स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी समेत सारी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहां से स्पेशलिस्ट अस्पतालों की कनेक्टिविटी की गई है। उन्होंने कहा, ह्लस्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। मैं बहुत खुश हूं कि आज बार सदस्यों और स्टाफ के लिए बहुत अच्छी सुविधा की शुरूआत हुई है। मैं दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज और आरएमएल (आरएमएल) अस्पताल सहित विशिष्ट अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड सुविधाओं से सीधा जुड़ाव है। इससे पहले 17 सितंबर 2024 को पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (डीजीएचसी) का उद्घाटन किया गया था।त

कनॉट प्लेस में आज सीजेपी का तिरंगा मार्च

दिल्ली में भारी सुरक्षा; चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च निकालने जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आस-पास अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियों ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है और चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)

फाईल फोटो

सीजेपी यह मार्च शाम 5 बजे निकाले जा रही है। सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके इसका ऐलान किया है। दीपके ने कहा है कि संगठन के सह-संयजोक सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में यह मार्च निकाला जाएगा। सीजेपी ने इस मार्च को 'लहरा दो तिरंगा' नाम दिया है।

कानून व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए पुलिस मुख्य जगहों पर जवानों की तैनाती करेगी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को रोकने लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि कनॉट प्लेस विरोध प्रदर्शन करने वाली जगह नहीं है।

विरोध प्रदर्शन वाली जगह से डिनोटिफाई जंतर-मंतर

पुलिस ऑफिस ने कहा 'जंतर-मंतर को निर्धारित विरोध प्रदर्शन वाली जगह की सूची से डिनोटिफाई कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी मंजूरी मिलने के बाद रामलील मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और जीबीडी ग्राउंड पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।

क्यों निकाला जा रहा तिरंगा मार्च?

आपको बता दें यह मार्च सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के विरोध में है। इससे पहले सीजेपी ने गुरुवार को इस मार्च का एलान किया था मगर इसे टाल दिया गया। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया था।

पुलिस के अनुसार, वे जंतर-मंतर में कथित तौर पर प्रवेश कर गए थे और इस दौरान तिरंगा लहराया, जिसे विरोध प्रदर्शन के लिए सरकार ने आधिकारक तौर पर डिनोटिफाई किया जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीजेपी संयोजक अभिजीत दीपके ने दास और रांका की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने ही देश में तिरंगा लहराने पर जेल भेजा रहा है।

महीने भर दिल्ली में 20 हजार जवान

आम आदमी पार्टी ने सीजेपी के तिरंगा मार्च को समर्थन दिया है। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया और दूसरे संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए अर्धसैनिक बलों के 20 हजार जवान महीनेभर सुरक्षा में तैनात हैं। अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, आगामी त्योहारों को देखते हुए भी जवानों को रोका गया है। आपको बता दें कि सीजेपी ने शुक्रवार शाम 5 बजे अन्य शहरों में भी तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है।

सीजेपी के तिरंगा मार्च को आप का समर्थन, गिरफ्तारी के विरोध में कनॉट प्लेस की सड़कों पर उतरेंगे कॉकरोच

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च को समर्थन दिया है। यह मार्च शाम 5 बजे निकाला जाएगा। तिरंगा मार्च सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के विरोध में होने जा रहा है। इससे पहले सीजेपी ने गुरुवार को इस मार्च का एलान किया था मगर इसे टाल दिया गया।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश

नई दिल्ली, 30 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहे और कई इलाकों में तेज गरज के साथ तेज बारिश हुई। इसे देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आगे भी बारिश, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को भी दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया है, जिससे संकेत मिलता है कि यह गीला मौसम एक दिन और जारी रह सकता है। आईएमडी ने उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी दी थी, जिसके साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 60 किमी प्रति घंटे तक के झोंके आ सकते हैं। राजधानी के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

यह ऑरेंज अलर्ट मौसम में अचानक आए बदलाव के बीच आया है, जिससे पिछले कुछ दिनों की गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी ने दिन भर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जो इस हफ्ते की शुरूआत में दर्ज तापमान से कम है।

यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी है, जो भारत के पश्चिम के क्षेत्रों से पूर्व की ओर बढ़ने वाली एक मौसम प्रणाली है और देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें ला सकती है। आगे भी दिल्ली और आसपास के इलाकों, जिनमें नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद शामिल हैं, में बारिश हो सकती है। हालांकि, बारिश की तीव्रता और वितरण क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार, 17 अक्टूबर से मौसम शुष्क होने की संभावना है। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, और अधिकतम तापमान बढ़कर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रविवार को मौसम मुख्य रूप से साफ होने की संभावना है और दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सड़कों पर जलभराव से पीक आवर्स के दौरान यात्रियों की रफ्तार भी धीमी हो सकती है।

जातिसूचक टिप्पणी के मामले में तत्काल सुनवाई का महिला पत्रकार का अनुरोध खारिज

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस महिला पत्रकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसने जंतर-मंतर के पास इस महीने की शुरूआत में एक प्रदर्शन के दौरान जातिसूचक टिप्पणी करने और सार्वजनिक रूप से अपमान करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज मामले में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया है। इससे पहले पत्रकार ने दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त (एसीपी) विवेक भगत के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने पर सहमति जताई। पत्रकार के वकील ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उनके मुवक्किल के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

आप प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस पर लगाया प्रदर्शन के दौरान जानलेवा हमला करने का आरोप

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने हाल के प्रदर्शनों के दौरान उन पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त को लिखित में शिकायत दी।

भारद्वाज ने मांग की कि आपराधिक साजिश के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए और उस समय तैनात दिल्ली पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा उन पर किए गए खतरनाक और जानलेवा शारीरिक हमले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। भारद्वाज ने अपने पत्र में कहा, मैं दिल्ली में सार्वजनिक सभाओं के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा मुझ पर किए गए शारीरिक हमले की तीन बेहद गंभीर और खतरनाक घटनाओं के संबंध में औपचारिक एवं समेकित शिकायत दर्ज कराने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। इन हमलों की प्रकृति, उन्हें अंजाम देने के तरीके और उनकी पुनरावृत्ति से स्पष्ट होता है कि ये भीड़ को नियंत्रित करने के सामान्य उपाय नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इसके बजाय, ये आधिकारिक ड्यूटी की आड़ में उन्हें गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने या उनकी जान लेने के लिए रची गई समन्वित आपराधिक साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो वह अदालत का रुख करेंगे। पिछले सप्ताह कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शन के आह्वान के दौरान, जब भारद्वाज और आप के अन्य नेताओं ने जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

जेएनयू यौन उत्पीड़न मामला: कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए गुरुवार को बुलाया है।

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर 11 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों के अनुसार, यह एफआईआर वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में सीटी स्कैन और टेस्ला एमआरआई मशीनों का शुभारंभ किया

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में ड्यूल सोर्स 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन और तीन टेस्ला एमआरआई मशीनों का शुभारंभ किया।

एलएनजेपी अस्पताल में मशीनों के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इन मशीनों के शुभारंभ से हृदय, मस्तिष्क, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच की बेहतर सुविधा अब अस्पताल में ही मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हों और बेहतर इलाज हर नागरिक की पहुंच में हो।

इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी डॉ. पंकज कुमार सिंह और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी उपस्थित रहे।

दिल्ली के कालिंदी कुंज में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में कुछ हमलावरों ने एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। शुरूआती जांच में पता चला कि यह हत्या जेल में हुई पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए की गई है। अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की आगे की जांच चल रही है। मृतक शाहिद हुसैन शाहीन बाग के अबुल फजल एन्क्लेव-क्कका रहने वाला था। कालिंदी कुंज थाने के कांस्टेबल अवधेश उसे अपोलो अस्पताल ले गए।

दिल्ली भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल मदन लाल खुराना की जयंती के अवसर पर गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके राजनीतिक योगदान को याद किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, खुराना की पत्नी राज खुराना, ओ. पी. बब्बर, मूलचंद चावला, वेद व्यास महाजन सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को स्मरण किया।

अभिजीत दीपके-नेहा बोरा के सामने हंगामा

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दीपके, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स असोसिएशन (आइसा) की प्रमुख नेहा बोरा और अन्य को गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली के प्रेस क्लब में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोग विरोध करने पहुंच गए। पत्रकारों की भीड़ के बीच अचानक 'बंद करो, दफा हो जाओ' जैसी आवाजें आने लगीं। दीपके ने विरोध में उठी आवाजों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें 50-100 रुपये का नोट दे दीजिए। जिसके लिए वे आए हैं। 50-100 रुपये का नोट देकर बाहर कर दीजिए।

जंतर-मंतर पर अवैध तरीके से घुसने और बेल बॉन्ड के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किए गए सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका के समर्थन में सीजेपी ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के सेंट्रल पार्क में तिरंगा लहराने के लिए जुटने का ऐलान किया है। इसी को लेकर कई स्टूडेंट्स यूनियन और सिविल सोसाइटीज के साथ प्रेस क्लब में जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बारी-बारी से सभी नेता अपनी बात रख रहे थे। आइसा की प्रमुख नेहा बोरा इससे पहले अपनी बात खत्म कर पातीं, कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पत्रकारों से खचाखच भरे प्रेस क्लब के लॉन से ह्लबंद करो, दफा हो जाओह्व की आवाज आने लगी।

दिल्ली में 250 पार्क केवल महिलाओं के लिए

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। अब शहर के सभी 250 वार्डों में ऐसे पार्कों की पहचान की जा रही है, जिसमें सिर्फ महिलाओं को एंट्री दी जाएगी। इस दौरान इन पार्कों में बच्चों को भी एंट्री मिलेगी। इन पार्क के गेट पर महिला सुरक्षाकर्मी तैनात की जाएंगी और पार्क की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। इसके लिए एमसीडी की स्थायी समिति ने फैसला लिया है।

सीसीटीवी कैमरे से होगी मॉनिटरिंग

इस फैसले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि इन पार्कों में केवल महिलाएं और बच्चे आएं, इसके लिए पार्कों के गेट पर महिला सुरक्षा गार्ड को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही जगह-जगह पार्क में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

इस मामले पर बात करते हुए एमसीडी स्थायी समित के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि इन पार्कों में केवल महिलाओं और बच्चों को ही आने की अनुमति होगी। पार्कों में मिलने वाले सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए शर्मा ने बताया कि इनमें ओपन जिम, अलग-अलग वाशरूम और चेंजिंग रूम भी बनाए जाएंगे। इन सभी सुविधाओं का मकसद है कि महिलाएं इन पार्कों में खुद को सुरक्षित महसूस करें।

महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए फैसला

इस मामले पर बात करते हुए शर्मा ने बताया कि बीते दिनों आस्था कुंज पार्क में हुई गैंगरेप की घटना के बाद महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित महसूस करवाने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें दिल्ली के 250 वार्डों में केवल महिलाओं और बच्चों के एंट्री वाले पार्क घोषित किए जाएंगे।

एमसीडी करेगी सर्वे

इस दौरान हुई बैठक में समिति ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे सभी जोन में सर्वे करेंगे और ऐसे पार्कों और अन्य जगहों को चिह्नित करेंगे, जहां महिलाओं के लिए पार्क विकसित किए जा सकेंगे। हालांकि, इस मामले में स्थायी समिति ने को समयसीमा नहीं तय की है।

'खराब खाना देकर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते'

नई दिल्ली, 30 सितंबर (वेब वार्ता)। जामिया मिलिया इस्लामिया के हॉस्टल मेस में खराब गुणवत्ता का भोजन परोसे जाने के मामले में गंभीर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल मेस में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकते। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाला और स्वच्छ भोजन नहीं दिया जाता, तब तक उनसे अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पीठ ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दिल्ली के बुराड़ी में यमुना किनारे मृत मछलियां मिलीं

नई दिल्ली, 30 सितंबर (वेब वार्ता)। उत्तर दिल्ली में बुराड़ी के निकट यमुना किनारे संभवत: हजारों मछलियां मृत पाई गई हैं, जिससे नदी के पानी की गुणवत्ता और उसके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी।

सोसाइटी ने बुधवार शाम एक्स पर नदी के किनारे मृत पड़ी मछलियों की तस्वीरें और वीडियो साझा किये। सोसाइटी ने अपने ह्यएक्स प्रोफाइल में खुद को जागरूकता फैलाने वाले व्यक्तियों का एक समूह बताया है। इसने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी पता नहीं चला है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हरियाणा से नहरों के जरिये रासायनिक कचरा यमुना में छोड़ा जा रहा है। क्या इसका संबंध 12 अक्टूबर को हुई अम्लीय वर्षा से हो सकता है? सोसाइटी ने कहा कि मछलियों की मौत जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहे दबाव का संकेत हो सकती है और इसके संभावित कारणों में पानी की गुणवत्ता में गिरावट, पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम होना और जहरीले पदार्थों की मौजूदगी शामिल हैं। मछलियों की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ये तस्वीरें यमुना में प्रदूषण को लेकर लगातार बनी चिंताओं के बीच सामने आई हैं। नदी को साफ करने के बार-बार किये गये प्रयासों के बावजूद प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियां बरकरार हैं। पिछले साल मई में भी बुराड़ी में बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत होने की खबरें आई थीं। उस समय सामने आये दृश्यों में नदी में हजारों मृत मछलियां दिखाई दी थीं। स्थानीय लोगों ने इन मौतों के लिए हरियाणा से कथित तौर पर छोड़े गए रासायनिक कचरे को जिम्मेदार ठहराया था। उस समय आई खबरों में प्रदूषण का स्तर अधिक होने की बात भी कही गई थी।

कनॉट प्लेस में प्रदर्शन से ट्रैफिक और कारोबार प्रभावित होने की आशंका, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला

नई दिल्ली, 30 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस (सीपी) के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन करने से रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रदर्शन से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वरिष्ठ वकील सचिन पुरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) नितिन डब्ल्यू. साम्ब्रे के समक्ष यह मामला रखा। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य इलाके में होने वाले इस प्रस्तावित जमावड़े को रोकने के लिए तत्काल अंतरिम हस्तक्षेप की मांग की। पुरी ने बताया कि 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में विरोध-प्रदर्शन होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण पूरे कनॉट प्लेस इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग सकता है और व्यावसायिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन दशहरा वीकेंड के दौरान हो रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है।

वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस विरोध-प्रदर्शन के चलते पूरा कनॉट प्लेस इलाका बंद हो सकता है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी और वहां के दुकानदारों व अन्य कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इन दलीलों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इससे जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है। यह याचिका कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में सड़क विक्रेता का काम करने वाले अनिल कुमार गुप्ता ने दायर की है। उन्होंने मांग की है कि सीजेपी को सेंट्रल पार्क या किसी ऐसी जगह पर कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन, मार्च या जमावड़ा करने से रोका जाए, जिसे विरोध-प्रदर्शन के लिए तय नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता ने सेंट्रल दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों पर व्यापक रोक लगाने की भी मांग की है, ताकि जनजीवन और व्यावसायिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए। यह प्रस्तावित प्रदर्शन तब हो रहा है, जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से शुक्रवार शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने की अपील की है। वे पार्टी के सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बना रहे हैं। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ह्यएक्सह्ल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में बुधवार को दिपके ने प्रस्तावित आंदोलन को ह्यलहरा दो तिरंगाह्ल नाम दिया और लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

संक्षिप्त वार्ता

परसा पलईडीह स्कूल में मिशन शक्ति का जागरूकता कार्यक्रम

वेब वार्ता, कमर खान

गैसड़ी / बलरामपुर। मिशन शक्ति फेज 6 के अंतर्गत थाना कोतवाली गैसड़ी जनपद बलरामपुर की मिशन शक्ति टीम उच्च प्राथमिक विद्यालय परसा पलईडीह में पहुंचकर साइबर जागरुकता कार्यक्रम को प्रोजेक्टर के माध्यम लाइव दिखाया गया तत्पश्चात छात्राओं के लिए कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम किया गया तथा महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान डिजिटल बोर्ड के माध्यम से रक्षित टंडन द्वारा साइबर सुरक्षा के संबंध में प्रस्तुत जागरूकता कार्यक्रम छात्र-छात्राओं को दिखाया गया तथा उन्हें साइबर अपराधों से बचाव के महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, फर्जी कॉल एवं मैसेज, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े जोखिम, फर्जी लिंक, डळढ एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। साथ ही, उन्हें मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने, सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने तथा इंटरनेट का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

रंगारंग कार्यक्रम के साथ ईपीएफओ में हुआ हिंदी पखवाड़ा-2026 का समापन

वेब वार्ता,कानपुर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह- 2026 का भव्य आयोजन सिंघानिया मैनेजमेंट स्कूल ऑडिटोरियम किया गया। समारोह में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, कार्यालय के कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग तथा कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करना रहा।

हरदोई में कांग्रेस की गांधीवादी पदयात्रा

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं ने गांधी प्रतिमा, तिकुनिया पार्क से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक नंगे पैर गांधीवादी पदयात्रा निकाली। रघुपति राघव राजा राम भजन गाते हुए निकले कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय के बाहर कथित आपत्तिजनक प्रदर्शन, बैनर और राहुल गांधी के चित्र पर कालिख लगाए जाने तथा बाल विद्या भवन विद्यालय परिसर में कथित राजनीतिक गतिविधि आयोजित किए जाने के मामलों में कार्रवाई की मांग उठाई। पदयात्रा के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में उनके स्टेनो को दूसरा ज्ञापन दिया।

ललितपुर पुलिस का खौफ! पहली बार दोनों हाथ उठाकर खुद कोतवाली पहुंचा आरोपी

एसपी संजीव बाजपेयी की सख्त पुलिसिंग की चर्चा, सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। अपराधियों के मन में कानून का खौफ और पुलिस की सख्त कार्रवाई का दबाव किस हद तक असर डाल सकता है, इसकी एक अनोखी तस्वीर ललितपुर में सामने आई है। महिला का मंगलसूत्र छीनने के मामले में पुलिस आरोपी तक पहुंचती, उससे पहले ही वह खुद दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोतवाली पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी के दोनों हाथ ऊपर उठाकर दाखिल होने का घटनाक्रम कैद हुआ है।

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेयी के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के बीच सामने आए इस घटनाक्रम को खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान तो ललितपुर में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। इससे पहले की अवधि में भी किसी आरोपी के इस तरह खुद कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण करने की जानकारी नहीं है। ऐसे में यह घटनाक्रम जिले में चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहा है।

तीन पुलिस टीमें तलाश में जुटीं, आरोपी खुद पहुंच गया कोतवाली

मामला 11 अक्टूबर की सुबह का है। चौबयाना स्थित रघुनाथ जी मंदिर के पास सपना कुशवाहा का मंगलसूत्र छीनकर एक व्यक्ति फरार हो गया था। पीड़िता की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 1061/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2)/317(2) में अभियोग पंजीकृत किया।

घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गईं। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और साक्ष्य जुटाने के साथ संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस के मुताबिक, लगातार हो रही छानबीन और पकड़े जाने के डर से आरोपी आसिफ उर्फ अन्ना पुत्र महबूब खां, निवासी मोहल्ला चौबयाना, थाना कोतवाली, ललितपुर ने 15 अक्टूबर को खुद कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

इस घटनाक्रम की सबसे खास बात कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, जिसमें आरोपी दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोतवाली में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को डर था कि वह पकड़ा जाएगा। इसी आशंका के चलते उसने खुद पुलिस के सामने पहुंचने का फैसला किया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने 11 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे रघुनाथ जी मंदिर के पास अंधेरे का फायदा उठाकर महिला का मंगलसूत्र छीन लिया था और मौके से भाग गया था। घटना के बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच और पुलिस की कार्रवाई से घबराकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया।

पुलिस ने आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से छीना गया पीली धातु का मंगलसूत्र पेंडेंट बरामद किया। इसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

एसपी के निर्देशन में अपराधियों पर शिकंजा

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेयी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की। जनपद में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की सक्रियता, सीसीटीवी फुटेज की जांच और साक्ष्य संकलन पर जोर दिया जा रहा है। इस मामले में आरोपी का खुद कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण करना विशेष रूप से चर्चा में है। आमतौर पर पुलिस अपराधियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करती है, लेकिन यहां आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही खुद थाने पहुंच गया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोतवाली में दाखिल होते आरोपी की तस्वीर इस पूरे घटनाक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू बन गई है।

एसपी संजीव कुमार बाजपेयी के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के बीच हुई इस कार्रवाई को पुलिस की सक्रियता के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। अपराधियों के विरुद्ध सख्ती और कानून का प्रभावी क्रियान्वयन पुलिस की प्राथमिकता है। इस मामले में आरोपी का खुद सामने आकर आत्मसमर्पण करना इसी घटनाक्रम की सबसे खास बात है।

हीमोफीलिया ए से पीड़ित बच्चों के लिए वरदान बन रही हेमलिब्रा थेरेपी

वेब वार्ता, कानपुर। हीमोफीलिया ए से पीड़ित बच्चों के उपचार में एमिसिजुमैब (हेमलिब्रा) थेरेपी एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रही है। यह आधुनिक उपचार रक्तस्राव को कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसके उपयोग से बच्चों को बार-बार नसों के माध्यम से फैक्टर-8 के इंजेक्शन लगवाने की परेशानी से राहत मिल सकती है। इससे बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके परिवारों की उपचार संबंधी कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलती है।

हीमोफीलिया सोसायटी कानपुर के नोडल डॉ. यशवंत राव ने बताया कि कानपुर में अब तक सात ऐसे बच्चों को हेमलिब्रा थेरेपी दी जा चुकी है, जिन्हें पहले प्रत्येक सप्ताह फैक्टर-8 की आवश्यकता पड़ती थी। इन बच्चों में उपचार के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह थेरेपी रक्तस्राव की घटनाओं को कम करने तथा बच्चों को बेहतर और अधिक सामान्य जीवन जीने में सहायता प्रदान कर सकती है।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के प्रधानाचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय पर बीमारी की पहचान, नियमित चिकित्सकीय देखभाल और उचित उपचार अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को इस बीमारी के लक्षणों तथा उपलब्ध उपचार विकल्पों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

क्या है हेमलिब्रा थेरेपी?

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ अमितेश यादव ने बताया कि एमिसिजुमैब एक आधुनिक जैविक औषधि है, जिसे त्वचा के नीचे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया में फैक्टर-8 की भूमिका की नकल करके काम करती है। इसके कारण पारंपरिक फैक्टर-8 की तरह बार-बार नसों में इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता कम हो सकती है। शुरूआती खुराक के बाद चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार इसे प्रत्येक सप्ताह, दो सप्ताह या चार सप्ताह में एक बार दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह उपचार उन बच्चों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है, जिनके शरीर में फैक्टर-8 के विरुद्ध अवरोधक प्रतिरक्षी तत्व (इनहिबिटर) विकसित हो जाते हैं।

नितिन अग्रवाल ने किसान मेले का किया शुभारंभ

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। अतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस एवं राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर गुरुवार को सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, बिलग्राम चुंगी के निकट किसान मेला, कृषि ज्ञान संगोष्ठी एवं जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी दी गई। राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

प्रोजेक्ट अलंकार के तहत नवीन कक्षा-कक्ष का भूमि पूजन एवं शिलान्यास सम्पन्न

वेब वार्ता, कमर खान

बलरामपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रोजेक्ट अलंकार योजनांतर्गत गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भग

वतीगंज, बलरामपुर में नवीन कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में पूर्व राज्यमंत्री एवं बलरामपुर सदर विधायक श्री पल्टूराम तथा चेयरमैन प्रतिनिधि डी.पी.सिंह बैस ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर नवीन कक्षा-कक्ष के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस पहल को विद्यालय में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार तथा विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का हुआ आयोजन

कानपुर। चित्रकूट धाम, कानपुर एवं झाँसी मंडल की संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी-2026 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के परिसर में आयोजित की गई। गोष्ठी की अध्यक्षता एम०के० शन्मुगा सुन्दरम, प्रमुख सचिव, कृषि, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कृषी मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं कल्याणपुर विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार तथा महापौर श्रीमती प्रमिला पाण्डेय, महापौर, कानपुर नगर निगम विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही।

फामाकीलॉजी विभाग में ड्रग एडिक्शन विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन

वेब वार्ता, कानपुर

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के फामाकौलॉजी विभाग में ड्रग एडिक्शन (नशे की लत) एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग विषय पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. आर. सी. चौरसिया, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फामाकौलॉजी विभाग, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज ने व्याख्यान प्रस्तुत किया।

व्याख्यान के दौरान डॉ. चौरसिया ने ड्रग एडिक्शन के विभिन्न पहलुओं, इसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया

कि ड्रग एडिक्शन एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या है, जो व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में लत की शुरूआत जिज्ञासा, दोस्तों के दबाव, घर के माहौल और पढ़ाई और पारिवारिक तनाव से होती है, इसके अलावा उन्होंने नशे की लत से ग्रसित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने तथा वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से समाज में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के फामाकौलॉजी विभाग के समस्त संकाय सदस्य एवं सभी स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस अतिथि व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत नशे की लत के प्रति वैज्ञानिक समझ विकसित करना तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम एवं नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरुकता को प्रोत्साहित करना था।

किसान की जमीन का विवाद या पत्रकारों को फंसाने की साजिश? बांदा प्रेस ट्रस्ट ने खोला मोर्चा

वेब वार्ता, बांदा। किसान की जमीन पर कथित कब्जे के विवाद से शुरू हुआ मामला अब पुलिस विवेचना की निष्पक्षता और पत्रकारों की स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर सवालों के केंद्र में है। गुलमोहर इको विलेज रिजॉर्ट से जुड़े भूमि विवाद में मुकदमा संख्या 187/2026, थाना नरैनी की कार्रवाई को लेकर बांदा प्रेस ट्रस्ट ने मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच, विवेचना दूसरे जनपद से कराने और पत्रकार रामकिशोर उपाध्याय को कथित रूप से फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की आशंका की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

पत्रकारों का सवाल है कि यदि मामला किसान की जमीन पर कथित कब्जे और कहासुनी से जुड़ा था, तो मुकदमे की धाराओं में बदलाव, एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में वृद्धि और खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकार को नोटिस जारी किए जाने के पीछे क्या तथ्यात्मक एवं कानूनी आधार था? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। एसपी कार्यालय में बयान लेने और खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार पर कार्रवाई क्यों?

इस प्रकरण में पत्रकार रामकिशोर उपाध्याय को नोटिस जारी किए जाने का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया है।

सीओ नरैनी की भूमिका पर उठे सवाल, दूसरे जनपद से जांच की मांग

ज्ञापन में क्षेत्राधिकारी नरैनी प्रवीण यादव की भूमिका और विवेचना की प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। धाराओं में वृद्धि के आधार, साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान तथा पत्रकारों को नोटिस जारी करने की परिस्थितियों की बिंदुवार जांच की मांग उठाई गई है। बांदा प्रेस ट्रस्ट ने मांग की है कि मुकदमा संख्या 187/2026 की विवेचना वर्तमान जनपद से बाहर किसी सक्षम एवं निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाए, ताकि जांच की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का समाधान हो सके। जरूरत के अनुसार संबंधित अवधि के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण भी विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत कराया जाए।

शिकायत के अनुसार, रामकिशोर उपाध्याय ने पुलिस अधीक्षक, बांदा के कार्यालय में पहुंचकर संबंधित व्यक्तियों के बयान लिए और मामले से जुड़ी खबरें प्रकाशित की थीं। इसके बाद उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई सामने आई। इस घटनाक्रम ने पत्रकारों के बीच गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या समाचार संकलन, वीडियो रिकॉर्डिंग और जनहित से जुड़े मामले को सार्वजनिक करना किसी पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई का आधार बन सकता है? यदि नोटिस जारी करने के पीछे पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए; और यदि पत्रकारिता के कारण दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई है, तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।

पत्रकारों की मांग स्पष्ट है—निष्पक्ष जांच हो, तथ्यों को सामने लाया जाए और किसी भी पत्रकार को उसके पेशे के कारण प्रताड़ित किए जाने की पुष्टि होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो।

शपथ-पत्र ने बढ़ाए सवाल, तहरीर से लेकर विवेचना तक हो जांच

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मामले से संबंधित एक व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांदा को नोटरी शपथ-पत्र देकर प्रकरण को फर्जी बताए जाने की बात सामने आई है। इस कथित शपथ-पत्र और संबंधित वीडियो बयान को जांच में शामिल करने की मांग की गई है। पत्रकारों का कहना है कि प्रारंभिक तहरीर, बाद के बयान, मुकदमे में धाराओं का परिवर्तन, एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में वृद्धि और विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों का आमने-सामने परीक्षण होना चाहिए। यदि बयानों और पुलिस कार्रवाई में कोई विरोधाभास है, तो उसकी वजह स्पष्ट की जानी चाहिए। यह भी मांग की गई है कि घटनास्थल की वास्तविक स्थिति, किसान की जमीन के राजस्व अभिलेख, गवाहों के बयान तथा उपलब्ध वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जाए।

हरदोई में मिशन शक्ति 6.0: नवदुर्गा, नव संकल्प—हर बेटी में शक्ति, हर कदम पर सुरक्षा; सपनों को उड़ान, ठगों से सावधान का संदेश

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। नारी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के संकल्प के साथ हरदोई में मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के तहत गुरुवार को जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ह्यनवदुर्गा, नव संकल्प—हर बेटी में शक्ति, हर कदम पर सुरक्षाह्न और ह्यसपनों को उड़ान, ठगों से सावधानह्न के संदेश के साथ पुलिस टीमों ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, महिला सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम और आपातकालीन सहायता के प्रति जागरूक किया। अभियान के अंतर्गत सीएसएन पीजी कॉलेज, श्री डाल सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिहानी, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चांदपुर-बिलग्राम, लखनऊ पब्लिक स्कूल माधौगंज, गौतम बुद्ध पब्लिक इंटर कॉलेज टड़ियावां तथा श्री जानकी प्रसाद इंटर कॉलेज पत्सेनी-कछौना में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

साइबर ठगी से बचाव के बताए तरीके

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने सीएसएन पीजी कॉलेज में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। वहीं, थाना टड़ियावां क्षेत्र के गौतम बुद्ध पब्लिक इंटर कॉलेज में लिंक के माध्यम से साइबर जागरूकता कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की

जानकारी दी गई। श्री डाल सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एवं साइबर अपराध अन्वेषक डॉ. रक्षित टंडन के ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण कराया गया। थाना कोतवाली देहात पुलिस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

पुलिसकर्मियों ने विद्यार्थियों को आगाह किया कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपना ओटीपी, पासवर्ड और बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल शिकायत करने की भी सलाह दी गई। थाना कछौना क्षेत्र के श्री जानकी प्रसाद इंटर कॉलेज, पत्सेनी में मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम ने छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा से संबंधित वीडियो दिखाए। विद्यार्थियों को बताया गया कि डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। अनजान लिंक, संदिग्ध फोन कॉल और ऑनलाइन लालच के जरिए साइबर ठग लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे में बिना सत्यापन किसी के साथ व्यक्तिगत या बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता के लिए 1090, 112, 1076, 108, 102 और 1098 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन के बारे में भी बताया गया।

बेटियों को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संकल्प

थाना पिहानी पुलिस ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए और अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखने के प्रति सचेत किया गया। थाना बिलग्राम की साइबर टीम एवं मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, चांदपुर में छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव और महिला सुरक्षा की जानकारी दी। अभियान के माध्यम से बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। थाना माधौगंज की मिशन शक्ति टीम ने लखनऊ पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया। बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए पढ़ने की उम्र में फेरे नहीं का संदेश दिया गया। साथ ही संकट की स्थिति में पुलिस और संबंधित सहायता सेवाओं से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस का नोटिस

28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। अभिनेता ने हाल ही में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। अब उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान खान के पास अमेरिकी पासपोर्ट है। उन पर आरोप है कि भारतीय नागरिक नहीं होने के बावजूद उन्होंने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धाराओं, 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू की है। हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों पर अभिनेता का पक्ष और पुलिस की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान ने

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन में हुए थे शामिल

सोशल मीडिया पर पुलिस वैन में बैठे अपनी तस्वीर साझा की थी। इसके साथ उन्होंने लिखा था, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं।'

मीडिया से बातचीत में अभिनेता ने कहा था कि वह मुंबई के निवासी के तौर पर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाए जा रहे हैं और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं थी, बल्कि वह इन सवालों के जवाब जानना चाहते थे।

इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें देश से बाहर भेजने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) दर्जे और वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है। सोमैया ने इस संबंध में पुलिस को सबूत सौंपने का दावा भी किया था।

फिलहाल, मामले में पुलिस की कार्रवाई और अभिनेता को जारी नोटिस को लेकर आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है।

अंकिता भंडारी के माता-पिता की हिरासत पर भड़के खरगे, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस कार्रवाई को मोदी सरकार की कायरता और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा बताया। खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि न्याय की गुहार लगा रहे माता-पिता को हिरासत में लिया गया, जबकि भाजपा के एक नेता को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद से सम्मानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता का दमन सरकार की ताकत नहीं, बल्कि सवालों से बचने का प्रमाण है।

खरगे ने कहा कि अपनी बेटी को खो चुके माता-पिता के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए माता-पिता

अंकिता भंडारी के माता-पिता को गुरुवार तड़के दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें तिलक मार्ग पुलिस थाने से रिहा कर दिया गया। अंकिता के माता-पिता की मांग है कि सिक्किम के राज्यपाल के रूप में दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर तब तक रोक लगाई जाए, जब तक मामले में चल रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पूरी नहीं हो जाती। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, ज्योतिमणि और इमरान प्रतापगढ़ी ने पुलिस थाने के भीतर विरोध प्रदर्शन किया। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि अंकिता के लिए न्याय मांगने वालों को निशाना बनाया जा रहा है।

पवन खेड़ा ने सरकार से पूछे सवाल

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में गिरावट का संकेत बताया। उन्होंने दुष्यंत गौतम की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंकिता के माता-पिता न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।

खेड़ा ने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर गंभीर आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्हें संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि न्याय की मांग करने वालों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में न्याय की मांग करने वाले परिवार के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?

कांग्रेस ने न्याय की लड़ाई जारी रखने की कही बात

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि अंकिता के माता-पिता के साथ हुआ व्यवहार बेहद दुखद है और उनकी पार्टी इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि अंकिता भंडारी मामले की जांच पूरी होने तक राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे पर विचार किया जाए।

अंकिता भंडारी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि मामले में सीबीआई जांच जारी होने की बात कही गई है। अंकिता के परिवार की मांग है कि उन्हें न्याय मिले और मामले से जुड़े सभी सवालों का निष्पक्ष जांच के जरिए जवाब सामने आए।

कांग्रेस विधायक बोलते-बोलते रो पड़े, आत्मदाह की चेतावनी दे डाली

हल्द्वानी। उत्तराखंड में हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने अपनी और अपने परिवार की जान को गंभीर खतरा बताते हुए दावा किया है कि उनकी हत्या कराई जा सकती है। बुधवार शाम एक प्रेसवार्ता में वे भावुक होकर रो पड़े और शिकायत का समाधान न होने पर आगामी गैरसैण विधानसभा सत्र के दौरान आत्मदाह की चेतावनी दे डाली।

विधायक हृदयेश ने आरोप लगाया कि एक हैकरों का गिरोह पिछले काफी समय से 24 घंटे उन पर और उनके परिवार पर निगरानी रख रहा है। उनके फोन हैक किए गए हैं और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत वे अप्रैल 2025 में तत्कालीन एसएसपी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सुमित हृदयेश ने दावा किया कि हैकरों से राज्य का कोई भी नेता अछूता नहीं है। उन्होंने एक बड़े नेता द्वारा उन्हें धमकाने का भी जिक्र किया, जिसने बताया था कि उन्हें रात-रात में किन नेताओं से क्या बात करते हैं, इसकी पूरी जानकारी है। हालांकि, विधायक ने उस नेता का नाम उजागर नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण में प्रदेश

सरकार का किसी भी तरह से हाथ नहीं है।प्रेसवार्ता के दौरान विधायक ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और सोनू शर्मा को दोबारा पार्टी में शामिल करने की पुरजोर मांग की। उन्होंने यहां तक कहा कि पार्टी चाहे तो संजय नेगी को हल्द्वानी विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन उनकी पार्टी में वापसी कराई जाए। इस गंभीर मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर सुमित हृदयेश को एक होनहार, योग्य एवं गंभीर व्यक्तित्व का धनी बताते हुए उनके दावों को अत्यंत चिंताजनक करार दिया। रावत ने संगठित गिरोहों द्वारा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों के सामने पैदा की जाने वाली असहज परिस्थितियों और ऐसे गिरोहों को मिल रहे संभावित संरक्षण पर चिंता जताई। उन्होंने सुमित से धैर्य, साहस और संयम बरतने की अपील करते हुए इस कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया।

बिहार में कस्टम विभाग के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर की हत्या

मृतक को काफी करीब से आठ गोली मारी गई

पटना। बिहार के आरा में गुरुवार सुबह हथियारबंद अपरधियों ने कस्टम विभाग के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से इलाके में दहशत फैल गई। परिवार के सदस्यों ने भू-माफियाओं पर हत्या करने का आरोप लगाया है। यह घटना आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन कॉलेज गेट के समीप हुई। बताया गया कि मृतक को काफी करीब से आठ गोली मारी गई। छह गोली दाहिने से पेट-सीने के पास, एक गोली बाईं तरफ सीने के पास और एक गोली बाईं ओर गर्दन में लगी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल पूर्व अधिकारी को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बिहिया थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी 67 वर्षीय रामकुमार सिंह के रूप में हुई है। वह भागलपुर से 2015 में रिटायर्ड हुए थे। घटना के समय रामकुमार सिंह के राजेश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन कार में छिप जाने के कारण उनकी जान बच गई। राजेश कुमार ने बताया कि वो अपने पिता के साथ हर रोज सुबह टहलने के लिए रमना मैदान जाते थे। अपराधियों की ओर से जब पापा को गोली मारी जा रही थी, उस समय में मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, जिसके कारण मेरी जान बच गई।

धर्म परिवर्तन के बाद नहीं मिलेगा जाति के आधार पर आरक्षण

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और जाति आधारित आरक्षण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से जुड़े होने के आधार पर किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तन के बाद स्वतः आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। अदालत ने कहा कि जाति आधारित सामाजिक स्थिति और उससे जुड़े आरक्षण के अधिकार का दावा केवल पूर्व धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तमिलनाडु सरकार के धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी फैसले को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने संवैधानिक प्रावधानों और आरक्षण से जुड़े सिद्धांतों के आधार पर इस मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दी। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से जुड़े किसी व्यक्ति को मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी उसी आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। अदालत ने

स्पष्ट किया कि केवल पहले किसी आरक्षित वर्ग से संबंधित होने के आधार पर दूसरे धर्म में जाने के बाद आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मामला जाति आधारित सामाजिक पिछड़ेपन, धार्मिक पहचान और संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था के

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार

बीच संबंध से जुड़ा है। अदालत ने इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने लोगों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले से धर्म परिवर्तन के बाद जाति आधारित आरक्षण का दावा करने के मामले में संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित पात्रता नियमों के महत्व को रेखांकित किया गया है। आरक्षण से जुड़े मामलों में संबंधित वर्ग की संवैधानिक स्थिति और लागू कानूनी प्रावधान महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस फैसले को सभी प्रकार के आरक्षण और प्रत्येक धर्म परिवर्तन के मामले में एक समान नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

इकलौते विधायक के बाद भी चुनौती बन गए प्रशांत किशोर

सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए पद संभालने के छह महीने के भीतर ही नई राजनीतिक चुनौती सामने आ गई है। यह चुनौती न तो प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से है और न ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। बल्कि, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) अपने एक विधायक के दम पर मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में मिली जीत ने प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाने का एक नया मंच दे दिया है। उन्हे पद से हटाने की मांग भी कर दी।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत ने प्रशांत किशोर की चुनौती को और गंभीर बना दिया। यह सीट लगभग तीन दशकों से बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट

चौधरी के लिए यह पहला बड़ा चुनावी परीक्षण था, और हार ने विपक्ष को उनके जमीनी राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठाने का मौका दिया। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री से बिहार के लिए एक काबिल और चरित्रवान मुख्यमंत्री चुनने की अपील की।

प्रशांत किशोर की चुनौती अब केवल व्यक्तिगत हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के भीतर मतभेदों का भी फायदा उठा रहे हैं। गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। गठबंधन के भीतर असहमति का ताजा उदाहरण बिहार विधान परिषद चुनावों में देखने को मिला है। आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले इन चुनावों में जन सुराज पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिशों ने एनडीए के सहयोगी दलों के बीच तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जन सुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार सिंह का खुलकर समर्थन किया है। अनंत सिंह ने इसे नीरज कुमार के साथ अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता का परिणाम बताया है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध नीरज कुमार से है, न कि नीतीश कुमार या जेडीयू से।

विवाद सुलझाने के लिए एनडीए विधायकों की बैठक

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विवाद सुलझाने के लिए एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई और आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार न करने की चेतावनी दी, लेकिन मतभेद दूर नहीं हो सके। प्रशांत किशोर ने इस विवाद को और हवा देते हुए नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से मतदाताओं से नीरज कुमार के समर्थन की अपील करने की चुनौती दी।

होर्मुज में दो जहाज डूबे, समुद्र में बिखरा सामान लूटने की लगी होड़

तेहरान। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य तनाव का सीधा असर अब समुद्री व्यापार पर दिख रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हाल ही में हुई अलग-अलग घटनाओं में दो मालवाहक जहाज डूब गए हैं। इन हादसों में एक जहाज के चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि दूसरे जहाज पर सवार सभी 21 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। इन घटनाओं के बाद समुद्र में कंटेनरों से बिखरे सामान को लूटने के लिए लोग नावों से मौके पर पहुंच गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहाजों पर बढ़ते हमलों और ईरान की आक्रामक चेतावनियों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के भविष्य को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है।

सिंगापुर के झंडे वाला मालवाहक जहाज जीएफएस प्राइड होर्मुज जलडमरूमध्य के पास डूब गया। जानकारी के अनुसार, जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद उसमें आग लग गई और वह क्षतिग्रस्त हो गया। सिंगापुर के समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण के मुताबिक, जहाज पर सवार सभी 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, और इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली।

हिमाचल के काकती गांव में है मात्र 6 लोगों की आबादी

शिमला। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित काकती गांव अपनी बेहद कम आबादी के कारण खास है। इस गांव की कुल आबादी मात्र छह है। इतना ही नहीं, यहां एक ही पुश्तैनी घर में परिवार की कई पीढ़ियां रहती आई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पहाड़ी टीले पर बसा यह गांव काजा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। काकती गांव की पहचान यहां मौजूद पारंपरिक मिट्टी के घर और सादगी भरी जीवनशैली से जुड़ी है। परिवार की कई पीढ़ियां इसी पुश्तैनी घर में रह रही हैं। परिवार के छोटे भाई कलजंग टाकपा लामा बौद्ध भिक्षु हैं और काजा स्थित एक बौद्ध गोंपा में सेवाएं देते हैं। वहीं, बड़े भाई छेरिंग नामगयल अपनी पत्नी रिंगजिन यूडन के साथ गांव में रहते हैं। छेरिंग के बड़े बेटे सोनम छोपेल भी लामा हैं और कांगड़ा तथा मंडी जिले की सीमा के पास चौंतड़ा स्थित बौद्ध मंदिर में शिक्षा ले रहे हैं।

उनके दूसरे बेटे नवांग ज्ञालसन विशेष जरूरतों वाले व्यक्ति हैं, जबकि तीसरे बेटे नवांग कुंगा टैक्सी चलाकर आजीविका कमाते हैं। परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन से भी जुड़ा हुआ है। करीब 15 बीघा जमीन पर खेती करके वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। काकती गांव की एक बड़ी पहचान इसका पारंपरिक मिट्टी और पत्थरों से बना घर है। रिपोर्ट में इस घर की उम्र करीब 300 साल बताई गई है, जबकि परिवार के रहने वाले घर को लगभग 100 साल पुराना भी बताया गया है। इस अंतर की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। हिमालयी क्षेत्रों में पारंपरिक घर स्थानीय मौसम के अनुकूल बनाए जाते थे। मोटी मिट्टी की दीवारें सर्दियों में गर्माहट बनाए रखने और गर्मियों में घर को अपेक्षाकृत ठंडा रखने में मदद करती हैं।

स्पीति घाटी में सर्दियां बेहद कठोर होती हैं। भारी बर्फबारी और जमा देने वाली ठंड के कारण कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं और आसपास के इलाकों से संपर्क मुश्किल हो जाता है। ऐसे में परिवार को सर्दियों से पहले कई महीनों का राशन, दवाइयां, ईंधन और पशुओं के चारे का इंतजाम करना पड़ता है। यहां सर्दियों में जीवन चलाने के लिए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। काकती गांव तक सुविधाएं भी धीरे-धीरे पहुंचीं। वर्ष 2008 में यह सड़क से जुड़ा और 2011 में बिजली पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2025 में यहां बीएसएनएल की 4जी मोबाइल सेवा भी शुरू हुई। इससे गांव के लोगों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क करना आसान हुआ है। गांव से काजा सड़क मार्ग से करीब 10 किलोमीटर दूर है।

दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां और इंटरनेट बंद करने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

दिल्ली पुलिस बोली- कानून-व्यवस्था के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना जरूरी था

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने और मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने हलफनामे में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 9 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया गया। साथ ही, उन्होंने अपने खिलाफ जारी अवमानना नोटिस रद्द करने और अदालत के आदेश में बदलाव करने की मांग की है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को संसद मार्च की अनुमति देने से इनकार करना और प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में लेना कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर

हिंसा, संपत्ति को नुकसान और लोगों के घायल होने की घटनाओं को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए गए। पुलिस का कहना है कि वह किसी भी संगठन को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दे सकती।

गृह सचिव ने बताया कि दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर रायसीना हिल के चार किलोमीटर के दायरे में 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई थीं। वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाएं चालू थीं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने भी स्पष्ट किया कि मेट्रो पूरी तरह बंद नहीं की गई थी, बल्कि 45 स्टेशनों पर आवाजाही प्रतिबंधित की गई थी।

दरअसल, 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी ने प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में बैरिकेडिंग की गई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदियों पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया था कि सार्वजनिक सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय केवल आवश्यक नियंत्रण किए जाएं, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।

इस बीच, माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया, घसीटकर वाहन में डाला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने भी उन्हें परेशान किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। ब्रिटास ने उम्मीद जताई कि अदालत उनके पत्र और विपक्ष की याचिकाओं पर विचार करेगी। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े मुद्दों पर भी सुनवाई की मांग की।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के तहत 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनमें बड़ी संख्या में वैध मतदाता भी शामिल हैं। तिवारी ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि अदालत का फैसला लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा करने वाला होना चाहिए।

एसआईआर से संबंधित याचिकाओं और विपक्षी नेताओं की शिकायतों पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इस बीच, एनएसयूआई की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने की खबर भी सामने आई है। इंटरनेट बंदी, मेट्रो प्रतिबंधों और प्रदर्शनकारियों की हिरासत से जुड़े मामले में अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है।

कार्टून समाज को जागरूक करने के साथ सोचने और आत्ममंथन के लिए करता है प्रेरित : मुख्यमंत्री

प्रख्यात कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

रायपुर। कार्टून केवल हास्य और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज का सशक्त दर्पण है। यह गंभीर विषयों, सामाजिक परिस्थितियों और विसंगतियों को हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से सहजता से जनमानस तक पहुंचाने वाली प्रभावशाली रचनात्मक विधा है। कई बार जो बात हजारों शब्दों में कहना कठिन होता है, उसे एक प्रभावशाली कार्टून बड़ी सरलता और गहराई के साथ अभिव्यक्त कर देता है। कार्टून समाज को हंसाने के साथ सोचने, समझने और आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल-2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कला और साहित्य किसी भी समाज की चेतना के वाहक होते हैं। कार्टून इस दृष्टि से विशिष्ट कला है, जिसमें चित्र, विचार, हास्य और व्यंग्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। एक कार्टूनिस्ट अपने सूक्ष्म अवलोकन और रचनात्मक दृष्टि से सामाजिक घटनाओं को ऐसा स्वरूप देता है, जो लंबे समय तक लोगों की स्मृति में बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्टून जनभावनाओं, जनअपेक्षाओं और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्ति देने का भी सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने भारतीय कार्टून कला की समृद्ध परंपरा का उल्लेख करते हुए महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर.के. लक्ष्मण का प्रसिद्ध 'कॉमन मैन' केवल एक कार्टून चरित्र नहीं, बल्कि देश के सामान्य नागरिक की आशाओं, अपेक्षाओं, जिज्ञासाओं और चिंताओं की पहचान बन गया। स्वतंत्रता के बाद बदलते भारत और उसकी सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया, वह भारतीय पत्रकारिता और कार्टून कला की अमूल्य विरासत है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्टून कला को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे दूरस्थ अंचलों की प्रतिभाओं को भी अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और इस विधा से जड़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कार्टून फेस्टिवल-2026 में जयपुर के प्रख्यात कार्टूनिस्ट श्री अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कलाकार की दीर्घकालीन साधना और रचनात्मक योगदान का सम्मान पूरी कला विधा का सम्मान है और इससे नई पीढ़ी को उत्कृष्टता की ओर बड़ने की प्रेरणा मिलती है।

डिजिटल माध्यमों से छत्तीसगढ़ की लोककलाओं को दुनिया तक पहुंचाएं : राज्यपाल रमेन डेका

➤खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के 70वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोककलाओं जैसे पंडवानी, पंथी, राउत नाचा, सुवा नृत्य, कर्मा और बस्तर की जनजातीय नृत्य परंपराओं का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश की इस सांस्कृतिक थाती को मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश-विदेश के कोने-कोने तक पहुंचाया जाना चाहिए। राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय का 70वां स्थापना दिवस समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 70 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के सामूहिक योगदान का परिणाम बताया। राज्यपाल श्री डेका ने दानवीर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती द्वारा अपनी पुत्री राजकुमारी इंदिरा सिंह की स्मृति में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दिए गए ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संगीत मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है, जबकि नृत्य, चित्रकला और शिल्प समाज के इतिहास व संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि कला के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रतिभा के साथ-साथ धैर्य, निरंतर अभ्यास और समर्पण बहुत जरूरी है। साथ ही, उन्होंने कला को आजीविका और व्यवसाय से जोड़ने की संभावनाओं पर भी बल दिया।

ताजा खबर

संक्षिप्त

राज्यपाल ने की विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता इभानन साहू की सराहना

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोकभवन में विशेष ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता श्री इभानन साहू ने मुलाकात की। ऑटिज्म से प्रभावित आकांक्षा लायंस इंस्टिटयूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर के इस 22 वर्षीय छात्र ने हांगकांग में आयोजित स्पेशल ओलंपिक ईस्ट एशिया रीजनल बॉलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया है। राज्यपाल ने इभानन साहू की उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की। डेका ने कहा कि इभानन साहू की उपलब्धि अदम्य इच्छाशक्ति और कठोर परिश्रम का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनकी सफलता न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। राज्यपाल ने आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट रायपुर द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्था के शैक्षणिक कार्यो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने स्वेच्छानुदान मद से 10 कम्प्यूटर प्रदान करने की बात कही। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन धबलिया, निदेशक डॉ. साधना नायक, प्राचार्य श्रीमती प्रतिष्ठा शुक्ला, एच.एफ.ओ. श्री नित्यानंद जैसवाल, इभानन की माता श्रीमती तेजश्री साहू एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

बिलासपुर के दोनों सरकारी अस्पताल 10 साल के लिए निजी हाथों को

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा बिलासपुर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में निर्मित 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संचालित और रखरखाव करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पीपीपी मॉडल अस्पताल को 10 वर्षों के लिए बिलासपुर के कोनी में कुल 340 बिस्तरों वाले इन दोनों अस्पतालों को एक ही 10-वर्षीय लाइसेंस समझौते के तहत निजी डेवलपर, ऑपरेटर को संचालन और रखरखाव के लिए सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। अस्पताल में सरकारी योजनाओं (आयुष्मान भारत आदि) के लाभार्थियों और पूरी तरह निःशुल्क मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे। केवल 20 प्रतिशत बिस्तरों का उपयोग पेड मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी जैसी प्रमुख चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी।

बैठक में विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भूवनेश यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं संबंधित ऑपरेटर संस्था केपीएमजी के प्रतिनिधि शामिल

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिलेट फसलों के उपार्जन

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कोदो, कुटकी, रागी तथा मक्का के उपार्जन एवं फसल विविधीकरण, किसानों को प्रोत्साहित करने सहित अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में इन कृषि उत्पादों की आवश्यकता, उपार्जन तथा मिलेटस के उपयोग के संबंध में चर्चा हुई। इसके तहत स्कूलों में मध्यांह भोजन और महिला एवं बाल विकास के पोषक आहार कार्यक्रमों में आंगनबाड़ियों के माध्यम में वितरित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिविर में उपस्थित लोगों को करेंगे संबोधित, उप मुख्यमंत्री शर्मा भी होंगे शामिल

दंतेवाड़ा में विशाल दिव्यांग सहायता शिविर से वर्चुअली जुड़ेगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

रायपुर। बस्तर अंचल के दिव्यांगजनों एवं नक्सल आईईडी ब्लास्ट से प्रभावित जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दंतेवा?ा जिले में 15 से 17 अक्टूबर 2026 तक विशाल निःशुल्क दिव्यांग सहायता एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा स्थित पुलिस लाइन करली में आयोजित इस शिविर से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह वर्चुअल माध्यम से जुडेगे। इस दौरान वे शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करने के साथ ही नक्सल हिंसा एवं आईईडी ब्लास्ट से प्रभावित पीड़ितों से संवाद करेंगे। शिविर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे। शिविर में दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स, ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर का विशेष उद्देश्य बस्तर के दूरस्थ एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों तक आवश्यक सहायता पहुंचाना है। विशेष रूप से नक्सल हिंसा के कारण दिव्यांग हुए व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराकर उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह करेंगे नक्सल हिंसा पीड़ितों से संवादः केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह शिविर में वर्चुअल माध्यम से जु?कर दिव्यांगजनों एवं उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे नक्सल हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों से संवाद भी करेंगे और उनकी परिस्थितियों, समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी लेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी शिविर में उपस्थित होकर दिव्यांगजनों एवं नक्सल हिंसा से प्रभावित हितग्राहियों का प्रोत्साहन करेंगे।

तीन जिलों के दिव्यांगजन होंगे शामिल दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिलों में कुल 768 दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरण के लिए चिन्हांकित किया गया है। उपकरण वितरण के लिए मांग अनुसार चिन्हांकित हितग्राहियों में दंतेवा?ा जिले के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा जिले के 62 दिव्यांगजन शामिल हैं। शिविर में दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आईईडी ब्लास्ट से दिव्यांग हुए 30 हितग्राही होंगे लाभान्वित शिविर के लिए चिन्हांकित हितग्राहियों में नक्सल घटनाओं के दौरान आईईडी ब्लास्ट दुर्घटनाओं से दिव्यांग हुए 30 व्यक्ति भी शामिल होंगे। इन हितग्राहियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नक्सल हिंसा से प्रभावित इन व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण मिलने से अब उनके दैनिक जीवन आसान हो जाएगा। इससे उन्हें चलने-फिरने, दैनिक कार्यों को पूरा करने तथा आजीविका संबंधी गतिविधियों में भागीदारी ब?ाने में मदद मिलेगी। शिविर में दिव्यांगजनों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें दैनिक जीवन में अधिक सुविधा मिल सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 अक्टूबर को सुकमा एवं बीजापुर जिलों के दिव्यांगजन तथा नक्सल हिंसा से प्रभावित हितग्राही शिविर में शामिल होंगे। वहीं 16 अक्टूबर को दंतेवा?ा जिले के हितग्राहियों को शिविर में लाभान्वित करने की व्यवस्था की गई है। शिविर 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

सीएम साय की पहल से जशपुर में आवासीय विकास को नई गति

➤ कुनकुरी और जशपुर में बनेंगी दो आधुनिक आवासीय कॉलोनियां

➤अटल विहार योजना के तहत 51.48 करोड़ रुपये की लागत से 225 आवासों का होगा निर्माण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित, सुविधायुक्त और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री साय के गृह जिले जशपुर को आवासीय विकास के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। छत्तीसग? गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा अटल विहार योजना के अंतर्गत कुनकुरी विकासखंड के ग्राम गिनाबहार और जशपुर नगर के ग्राम बालाछापर में लगभग 51 करो? 48 लाख रुपये की लागत से दो आधुनिक आवासीय कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से कुल 225 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। इन योजनाओं से जिले में सुनियोजित आवासीय विकास को गति मिलने के साथ ही विभिन्न आय वर्गों के परिवारों को अपना घर प्राप्त करने के नए अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी के विशेष निर्देशों के अनुरुप इन परियोजनाओं को आगे ब?ाया जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आवासीय विकास केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि जिला मुख्यालयों, छोटे नगरों और विकासखंड स्तर तक भी आधुनिक एवं व्यवस्थित आवासीय सुविधाओं का विस्तार हो।

लोकतंत्र को मजबूत बनाने जिला प्रशासन की पहल, अंदरूनी गांवों तक पहुंच रहे बीएलओ

सुकमा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-90 कोंटा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रशासन का निर्वाचन अमला अंदरूनी एवं दूरस्थ गांवों तक पहुंचकर मतदाता सूची में नाम जु?वाने से छूटे पात्र नागरिकों की पहचान कर रहा है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म-6 वितरित कर नए मतदाताओं का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अवसर से वंचित न रहे। डिजिटल तकनीक, नियमित निगरानी और जनजागरूकता से अभियान को मिल रही गति देते हुए बीएलओ द्वारा ठस्व् ।चच एवं म्ब्प्छम्ज् के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन संबंधी जानकारी दर्ज की जा रही है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन अमले को प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं संबंधित तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मैदानी कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों में निर्वाचक साक्षरता क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों एवं युवाओं को मतदान के महत्व और मतदाता पंजीयन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं को अग्रिम आवेदन की सुविधा की जानकारी देकर भविष्य के मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने की पहल की जा रही है।

जशपुरनगर में 11.83 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाईटेक बस स्टैंड: विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में यात्री सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर जिला मुख्यालय जशपुरनगर में 11 करो? 83 लाख 62 हजार रुपये की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया जारी है। लगभग तीन एक? क्षेत्र में विकसित होने वाला यह आधुनिक बस टर्मिनल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ शहर की परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप देगा। लंबे समय से आधुनिक बस स्टैंड की प्रतीक्षा कर रहे जिलेवासियों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी। जशपुरनगर के वार्ड क्रमांक 8 स्थित पुराने मवेशी बाजार परिसर में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण प्रस्तावित है। लगभग तीन एक? क्षेत्र में विकसित होने वाले इस आधुनिक बस टर्मिनल में एक साथ 35 से 40 बसों के ख? होने की व्यवस्था होगी। इससे बसों के आवागमन और ठहराव को व्यवस्थित करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जशपुर जिला मुख्यालय का बस स्टैंड जिले के प्रमुख परिवहन केंद्रों में शामिल है। यहां प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है और पांच हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। यहां से जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अलावा प?ोसी राज्यों झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित अन्य स्थानों के लिए बस सेवाएं संचालित होती हैं। यात्रियों की ब?ती संख्या को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। नए बस स्टैंड के निर्माण से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी। 'वेटिंग हॉल, लिफ्ट और डिजिटल सूचना स्क्रीन सहित मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं' प्रस्तावित हाईटेक बस स्टैंड को यात्रियों की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा।

जशपुर जिले में 16 मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

सीएम के नेतृत्व में संवेदनशील राहत व्यवस्था दुर्घटना प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसग? सरकार दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संकट की घ?ी में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और उन्हें आर्थिक संबल देने की इसी पहल के तहत जशपुर जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 16 व्यक्तियों के निकटतम वारिसों के लिए कुल 64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटनाओं एवं आपदाओं के कारण अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप समय पर सहायता मिल सके। किसी परिवार के सदस्य की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न दुख और क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और जीवन को पुनः व्यवस्थित करने में सहायक होती है। कलेक्टर कार्यालय जशपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत 16 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इन प्रकरणों में कुएं, तालाब, नदी, बांध एवं अन्य जलस्रोतों में डूबने से हुई मृत्यु के मामले शामिल हैं। शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत पात्र निकटतम वारिसों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार कुनकुरी तहसील के ग्राम बेमताटोली में मनीषा बाई की कुएं में गिरकर डूबने से मृत्यु के प्रकरण में श्री ललकू राम के आवेदन पर 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जशपुर तहसील के ग्राम बाहमनपुर में बीकांत तिर्की की तालाब में डूबने से मृत्यु के मामले में श्री बरनाबास तिर्की के आवेदन पर 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सहसपुर लोहारा कॉलेज को दी 50 लाख के विकास कार्यों की सौगात

30 लाख के अतिरिक्त कक्ष का किया भूमिपूजन, बाउंड्रीवॉल और बालिका शौचालय के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की

रायपुर। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा के लिए अधोसंरचना मजबूत करने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के शासकीय गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा में 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का भूमिपूजन किया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में 15 लाख रुपए की लागत से बाउंड्रीवॉल तथा 5 लाख रुपए की लागत से बालिका शौचालय निर्माण कराने की घोषणा की। महाविद्यालय में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उन्हें अनुशासन, मेहनत और आधुनिक तकनीक के उपयोग से भविष्य संवारने के लिए प्रेरित किया।

अनुशासन और मेहनत से बनाएं भविष्य - उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवा शक्ति संवाद में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया कि युवा अपने लक्ष्य तय करें, अनुशासन में रहें और परिणाम की चिंता छोड़ मेहनत पर ध्यान दें। आधुनिक तकनीक सीखें, लेकिन उसके अधीन न हों। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज करियर बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है। विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे ब?ना चाहिए। श्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा क्षेत्र के स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अब महाविद्यालयों में भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पीएससी, एसएससी और यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण ख़बर

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में अपना खिताब बरकरार रखने उतरेगी भारतीय टीम

- नई दिल्ली। अनुभवी डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में उतरेगी। हॉकी इंडिया ने इस टूनार्मेंट के लिए 18 सदस्यीय टीम घोषित की है। ये टूनार्मेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में खेला जाएगा। इसमें भारतीय टीम का लक्ष्य अपना खिताब बरकरार रखना रहेगा। इसमें भारतीय टीम को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा।

हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने हाल में जापान में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है इसका लाभ भी उसे मिलेगा। इससे टीम अब टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत का सिलसिला बनाये रखना चाहेगी।।

हॉकी इंडिया ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस टूनार्मेंट में भी बरकरार रखा है। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संयोजन है। अनुभवी गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक की टीम में वापसी हुई है, वहीं युवा डिफेंडर अमनदीप लकड़ा और मिडफील्डर आदित्य अर्जुन ललागे को भी इस टीम में शामिल किया गया है।

विश्वकप में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका से रहना होगा सावधान : अश्विन

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने 2027 विश्व कप को लेकर कहा है कि इसमें मेजबान होने के कारण दक्षिण अफ्रीका प्रबल दावेदार रहेगी। इसके साथ ही अश्विन ने भारत की क्षमताओं पर भी अपनी बात की। अश्विन का मानना है कि भारतीय टीम में असाधारण प्रतिभा और काबिलियत है। उन्होंने विशेष रूप से तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह की भूमिका पर जोर दिया। अश्विन के अनुसार, यदि बुमराह अपनी पूरी लय में होते हैं, तो भारत के पास एक अनुभवी और बेहद प्रभावी तेज गेंदबाजी इकाई होगी जो किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसके साथ ही, भारत के पास उच्च-स्तरीय स्पिनरों की भरमार है, और अश्विन ने यह भी संकेत दिया कि कुछ मैदानों पर स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलेगी, जो भारतीय टीम के लिए एक अतिरिक्त लाभ होगा। बल्लेबाजी विभाग में भी, टीम के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, जो बड़े टूनार्मेंटों में दबाव को संभालने के लिए महत्वपूर्ण होता है और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने की क्षमता

रखता है।

हालांकि, भारत की इन मजबूतियों के बावजूद, अश्विन का मानना है कि 2027 विश्व कप में कुछ टीमें ऐसी होंगी जो भारत को कड़ी टक्कर देंगी, और इनमें से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को सबसे आगे रखा है। अश्विन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें दो-तीन टीमें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका उनमें से सबसे अच्छी है। उनकी राय में, दक्षिण अफ्रीका अपने घरेलू विश्व कप के लिए एक बेहद मजबूत दावेदार होगी, जो मेजबान देश को एक स्वाभाविक बढ़त दिलाता है।

उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की क्षमता का विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि, खासकर एसए20 जैसी लीग के बाद, वहां के खिलाड़ियों में घरेलू परिस्थितियों की गहरी समझ आ गई है। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी न केवल इन परिस्थितियों में जरूरी कौशल रखते हैं, बल्कि वे इन्हें अच्छी तरह समझते भी हैं। अश्विन ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के खेल की गुणवत्ता और उनकी एकजुटता की भी तारीफ की, यह कहते हुए कि क्रिकेट में वे एक बहुत मजबूत टीम हैं और एक इकाई के रूप में खेलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इस मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा।

अश्विन का यह आकलन दर्शाता है कि आगामी विश्व कप में मेजबान देश को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जहां भारतीय टीम अपनी काबिलियत और अनुभव के दम पर एक सशक्त दावेदार होगी, वहीं घरेलू माहौल और परिस्थितियों का गहरा ज्ञान दक्षिण अफ्रीका को एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण बढ़त दिलाएगा। 2027 वनडे विश्व कप भले ही अभी दूर हो, लेकिन अश्विन जैसे दिग्गजों की यह प्रारंभिक टिप्पणियां क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्साह जगा रही हैं और भविष्य के मुकाबलों की उत्सुकता बढ़ा रही हैं।

फीफा ने सदस्य देशों को दोगुनी से भी अधिक राशि देने प्रस्ताव रखा

हेग। विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्था (फीफा) ने साल 2027 से 2030 तक के दौरान अपने सदस्य देशों में फुटबॉल के विकास के लिए 6.35 अरब अमेरिकी डॉलर का एक कोष बनाने का प्रावधान रखा है। इसमे प्रत्येक राष्ट्रीय संघ को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग दो अरब, 37 करोड़ रुपए) की बढ़ी हुई धनराशि मिलेगी। यह राशि वर्तमान में मिलने वाली धनराशि से दोगुनी से भी अधिक है। इससे सदस्य देशों में तेजी से खेल का विकास हो सकेगा।

फीफा द्वारा जारी एक दस्तावेज में बताया गया है कि यह वित्तीय पहल हाल ही में संपन्न हुए विश्व कप में मिली जबरदस्त व्यावसायिक सफलता से उत्साहित होकर की जा रही है। इस संस्था का लक्ष्य इस आय का उपयोग

अपने 211 सदस्य संघों, परिसंघों और अन्य हितधारकों में फुटबॉल विकास में निवेश बढ़ाने के लिए करना है। इससे पहले, प्रत्येक फुटबॉल संघ को चार साल की अवधि के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलते थे, जिससे यह प्रस्तावित वृद्धि फुटबॉल के जमीनी स्तर से लेकर पेशेवर स्तर तक के विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी।इस दस्तावेज में आगे कहा गया है कि फीफा ने अपने वित्तीय भंडार से कुल 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि सदस्य देशों में वितरित करने का प्रस्ताव रखा है। जो विश्व कप की शानदार सफलता को दिखाता है। यह योजना सदस्य देशों को बुनियादी ढांचे के विकास, युवा कार्यक्रमों, महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने और कोचिंग व प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगी।इस महत्वपूर्ण वित्तीय योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी गई है। इसे दिसंबर 2026 में फीफा परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद मार्च 2027 में आयोजित होने वाली 77वीं फीफा कांग्रेस में इसे अंतिम मंजूरी प्रदान की जाएगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में रबाडा कर सकते हैं वापसी : बावुमा

जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम के मुख्य तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा फिट हो जाएंगे। कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा कि रबाडा पहले से ठीक दिख रहे हैं। तीन मैचों की सीरीज का ये मुकाबला 18 से 22 अक्टूबर तक गकेबरहा के सेंट जॉर्ज्स पार्क में खेला जाएगा। पहला टेस्ट 214 रनों से हारने के बाद अफ्रीकी टीम के लिए मैच में वापसी बेहद अहम जरुरी जा रही है, क्योंकि वे सीरीज में वापसी की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।

रबाडा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, पहले टेस्ट में चोट के कारण वह अंतिम ग्यारह में शामिल नहीं किये गये थे। कप्तान बावुमा ने बताया कि यह फैसला पूरी तरह से ऐहतियात के तौर पर लिया गया था, जिससे उन्हें अपनी फिटनेस में सुधार के लिए कुछ अतिरिक्त दिन मिल सकें। गौरतलब है कि गकेबरहा में होने वाला यह

मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद अहम है। पहले टेस्ट में मिली करारी हार ने टीम की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए थे पर रबाडा की वापसी से उनकी गेंदबाजी आक्रमण को एक नई धार मिलने की उम्मीद है। रबाडा पिछले एक साल में फिटनेस को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। इसके अलावा, उन्होंने इस साल मई में टी20 लीग (आईपीएल) फाइनल में भी खेला था, जो उनकी मैच फिटनेस का संकेत देता है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबलों में हमेशा प्रभावी रहे हैं, और उन्होंने अतीत में महत्वपूर्ण मौकों पर टीम के लिए पांच विकेट हॉल भी लिए हैं, जो उनकी काबिलियत दिखाता है।

यदि रबाडा की वापसी होती है, तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि किस खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा। पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने दो विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों - मार्को यानसन और एनरिच नॉर्खिया को मैदान में उतारा था। उनके साथ तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर वियान मुल्डर भी टीम का हिस्सा थे। मुल्डर और यानसन दोनों ही बल्ले से भी उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखते हैं, जिससे वे टीम में अपनी जगह लगभग सुनिश्चित कर लेते हैं। ऐसे में, एनरिच नॉर्खिया के बाहर होने की संभावना सबसे अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि टीम को एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज की आवश्यकता है जो रबाडा के साथ नई गेंद से मोर्चा संभाल सके।

एकदिवसीय में सर्वाधिक छक्के: धोनी और रोहित शीर्ष कप्तानों में शामिल

मुंबई। एकदिवसीय क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और छक्कों की बौछार से मैच का रुख बदलने वाले शीर्ष पांच कप्तानों में भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा का नाम प्रमुखता से शामिल है। इस विशिष्ट सूची में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में सफेद गेंद क्रिकेट में क्रांति ला दी।

मोर्गन ने बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाकर एक मानदंड स्थापित किया है। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने एक नया आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया। 2011 से 2022 के बीच, मोर्गन ने 126 एकदिवसीय मैचों में कप्तानी की और 115 पारियों में कुल 147 छक्के जड़े। यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने दो देशों (आयरलैंड और इंग्लैंड) के लिए एकदिवसीय क्रिकेट खेला। अपनी कप्तानी के दौरान, मोर्गन ने 44.03 की बेहतरीन औसत और 96.00 के स्ट्राइक रेट से 4,403 रन बनाए, जिसमें 9 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं। उनका 148 रनों का सर्वोच्च स्कोर उनकी विध्वंसक क्षमता को दर्शाता है।

भारतीय क्रिकेट के दो महान कप्तान, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, इस सूची में संयुक्त रूप से दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, दोनों के नाम 126 छक्के दर्ज हैं। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी ने 2007 से 2018 के बीच 200 एकदिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी की और 172 पारियों में 126 छक्के लगाए। धोनी न केवल छक्के मारने में माहिर थे, बल्कि वे मैच को अपनी शर्तों पर खत्म करने वाले बेहतरीन फिनिशर भी थे। उन्होंने 48 बार नाबाद लौटते हुए 53.55 की बेमिसाल औसत से 6,641 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 47 अर्धशतक

शामिल हैं। उनके प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर शॉट्स आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में ताजा हैं। वहीं, हिटमैन के नाम से लोकप्रिय रोहित शर्मा ने धोनी के बराबर 126 छक्के लगाए हैं, लेकिन उन्होंने यह कारनामा कहीं कम मैचों में किया है। 2017 से अब तक, रोहित ने मात्र 56 मैचों की 55 पारियों में कप्तानी करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। रोहित का विस्फोटक अंदाज उनकी पहचान है, जिन्होंने 111.97 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट और 52.20 की औसत से 2,506 रन बनाए हैं, जिसमें एक ऐतिहासिक दोहरा शतक (208 रन) और 5 शतक शामिल हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में चौकों (251) से कहीं ज्यादा छक्कों पर भरोसा दिखाया, जो उनकी आक्रामक खेल शैली का प्रमाण है।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को अपनी कप्तानी में दो विश्व कप जिताने वाले दिग्गज रिकी पोंटिंग इस सूची में चौथे स्थान पर काबिज हैं। 2002 से 2012 तक 230 मैचों में नेतृत्व करते हुए, पोंटिंग ने 220 पारियों में 123 छक्के लगाए। बतौर कप्तान सर्वाधिक 8,497 रन (42.91 की औसत से) बनाने वाले पोंटिंग ने 22 शतक भी जमाए, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका के मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स इस लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। 2012 से 2017 के बीच 103 मैचों में कप्तानी करते हुए, डिविलियर्स ने 98 पारियों में 118 छक्के जड़े। मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की अपनी अनूठी क्षमता के साथ, उन्होंने 63.94 की अविश्वसनीय औसत और 110.48 की स्ट्राइक रेट से 4,796 रन बनाए। कप्तान के रूप में उनके नाम 13 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हैं, जिसमें उनका 162 रनों का नाबाद स्कोर वनडे की सबसे आक्रामक पारियों में से एक है।

कारोबार

कच्चे तेल में गिरावट, आईटी शेयरों में उछाल से शेयर बाजार में तेजी

मुंबई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की मजबूती के दम पर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल देखा गया। शुरूआती कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक उछलकर 73,798 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 22,900 का आंकड़ा पार कर गया। इस तेजी को आईटी सेक्टर से मजबूत समर्थन मिला, हालांकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। घरेलू शेयर बाजारों को आज कई सकारात्मक संकेतों से मजबूती मिली। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और भारतीय रुपये के मजबूत होने से निवेशकों का मनोबल बढ़ा। पूर्वाह्न 10:26 बजे तक, बीएसई सेंसेक्स 928.62 अंकों की बढ़त के साथ 73,710.51 पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 274.65 अंकों के साथ 22,897.35 पर था। इंट्रा-डे में सेंसेक्स ने 73,798.59 और निफ्टी ने 22,919.60 के उच्च स्तर को छुआ। हालांकि, बाजार की इस शानदार तेजी के बावजूद, व्यापक स्तर पर बिकवाली का दबाव देखा गया। निफ्टी मिडकैप 100 में करीब आधे फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में लगभग एक फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। बाजार को सबसे मजबूत सपोर्ट आईटी सेक्टर से मिला। दक्षिण कोरियाई इंडेक्स कोस्पी में एआई स्टॉक्स में भारी बिकवाली के चलते लगभग 9 फीसदी की गिरावट आई, जिससे निवेशकों ने आईटी सर्विसेज स्टॉक्स में खरीदारी का रुख किया। इसका नतीजा यह हुआ कि घरेलू मार्केट में निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 फीसदी से अधिक उछल गया और बाद में 1.6 फीसदी की बढ़त पर कारोबार कर रहा था। टीसीएस, टेक महिंद्रा और इंफोसिस जैसे दिग्गज आईटी शेयरों में 1-2 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखी गई। इस तेजी ने पीएसयू बैंकिंग शेयरों की बिकवाली के दबाव को काफी हद तक संभाल लिया, जिनका निफ्टी इंडेक्स 2 फीसदी से अधिक टूटा था। प्राइवेट बैंकों से भी मार्केट को समर्थन मिला, और निफ्टी प्राइवेट बैंक एक फीसदी से अधिक मजबूत हुआ। आईटी के अलावा, एफएमसीजी और फाइनेंशियल्स सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिली। दूसरी ओर, सरकारी बैंक, एनर्जी और मेटल शेयरों में मुनाफावसूली का दौर जारी रहा। एनएसई पर निफ्टी पीएसयू बैंक और एनर्जी इंडेक्स 1-1 फीसदी से ज्यादा टूट गए। निफ्टी में हिंडाल्को का शेयर 1.2 फीसदी फिसलकर टॉप लूजर रहा, जबकि ओएनजीसी, ट्रेंट और बीएसई के शेयरों में भी कमजोरी दर्ज की गई।

भारत की जीडीपी कार्यप्रणाली को आईएमएफ का समर्थन, कहा- 'विकास का स्वागत'

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने गुरुवार को भारत की अद्यतन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गणना कार्यप्रणाली का समर्थन किया। आईएमएफ ने कहा कि यह कार्यप्रणाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप है। यह आईएमएफ की सलाह के पूरी तरह सुसंगत है। आईएमएफ के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने इसे 'स्वागत योग्य कदम' बताया। उन्होंने बैंकॉक में पत्रकारों से कहा कि अद्यतन कार्यप्रणाली आईएमएफ के सांख्यिकी विभाग की सलाह से पूरी तरह मेल खाती है। श्रीनिवासन ने यह भी बताया कि भारत ने जीडीपी कार्यप्रणाली में संशोधनों को समझाने के लिए एक नोट जारी किया था। उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अच्छे काम को सराहा।

क्या आईएमएफ भारत की जीडीपी कार्यप्रणाली से सहमत है?

आईएमएफ के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया कि जीडीपी कार्यप्रणाली में संशोधन उनकी सलाह के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया है, वह अच्छी कार्यप्रणालियों के सुसंगत है। श्रीनिवासन ने सुधार की गुंजाइश

स्वीकार की, लेकिन एमओएसपीआई के प्रयासों की सराहना की। आईएमएफ के सांख्यिकी विभाग ने भी इस कार्यप्रणाली को समर्थन दिया है। आईएमएफ के अधिकारी ने कहा कि भारत ने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ ऊर्जा संकट का सामना किया। भारत ने इस संकट पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह भी कहा कि विनिमय दर पर दबाव को आर्थिक विफलता का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। विनिमय दर वैश्विक ब्याज दरों, निवेशक जोखिम लेने की प्रवृत्ति और तेल कीमतों का कार्य है। विनिमय दर पर दबाव का वृद्धि से वास्तविक अलगाव नहीं है।

जीडीपी आंकड़ों पर हालिया राजनीतिक विवाद क्या था?

पिछले महीने, जून तिमाही के लिए 7.8 फीसदी की उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पूर्व वित्त सचिव एस सी गर्ग ने इन आंकड़ों को चुनौती दी थी। गर्ग ने दावा किया कि पिछले वर्ष के आंकड़ों को कम करके जीडीपी आंकड़ों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया था। विपक्षी दलों ने गर्ग के दावों को भुनाया और सरकार के जीडीपी आंकड़ों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गर्ग के दृष्टिकोण को 'चुनिंदा आंकड़ों का उपयोग' बताया। उन्होंने कहा कि नवीनतम जीडीपी आंकड़े मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष को नए आधार के रूप में उपयोग करके संकलित किए गए थे। कार्यप्रणाली में बदलाव के कारण पिछले वर्ष के तिमाही आंकड़ों में संशोधन हुए थे।

अमेरिका से दूरी, भारत-कनाडा की व्यापार समझौते की तैयारी पूरी

नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच इस साल के अंत तक एक बड़ा व्यापार समझौता संभव है। कनाडा की ओर से इस डील को पूरा करने के लिए अब जल्दबाजी भी देखी जा रही है। खासकर अमेरिका की तरफ से कनाडा पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) के प्रभावी होने के बाद से। इसी कड़ी में कनाडा ने 30 साल से भी ज्यादा समय के बाद भारत में अपना सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजा है। इस दल में करीब 300 व्यापारी और अधिकारी शामिल हैं, जो कि भारत और कनाडा के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) करने की भी तैयारी करेंगे।

भारत के वाणिज्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष

2025-26 में करीब 8 अरब डॉलर (7.95 अरब डॉलर) का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इसमें भारत की ओर से कनाडा को होने वाले निर्यात 4.67 अरब डॉलर था, जबकि कनाडा से आयात का आंकड़ा 3.28 अरब डॉलर का था।

भारत और कनाडा के बीच बीते पांच वित्त वर्षों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सामने आता है कि जहां 2021 से 2024 के बीच दोनों देशों का व्यापार लगातार बढ़ता रहा तो वहीं 2024 के बाद इसमें कमी आने लगी। इसकी एक बड़ी वजह दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट रही। दरअसल, जून 2023 में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारे से निकलते वक्त हत्या हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसके लिए बिना सबूत दिए ही भारत पर आरोप लगा दिए थे। नतीजतन दोनों देशों के बीच न सिर्फ राजनयिक रिश्ते, बल्कि व्यापारिक रिश्तों पर भी बड़ा ब्रेक लग गया और आयात-निर्यात दोनों के ही आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई।

हालांकि, मार्च 2025 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से हटने और मार्क कार्नी के पीएम बनने के बाद से कनाडा ने एक बार फिर भारत से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाए। नतीजतन दोनों देशों का व्यापार एक बार फिर संतुलित स्तर पर आ चुका है। इसी कड़ी में अब दोनों देश अपने रिश्तों को एक व्यापार समझौते के जरिए और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

रुपया 31 पैसे चढ़कर 94.86 प्रति डॉलर पर खुला

मुंबई। रुपया गुरुवार के कारोबारी दिन 31 पैसे मजबूत होकर 94.86 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। बाजार के जानकारों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विदेशी मुद्रा बाजार में किए जा रहे संरचनात्मक हस्तक्षेप और नकदी सख्त करने के उपायों से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.95 प्रति डॉलर पर खुला। इसके बाद यह और मजबूत होकर 94.86 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 31 पैसे की बढ़त है। रुपया बुधवार को 19 पैसे मजबूत होकर 95.17 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दशार्ने वाला डॉलर सूचकांक 0.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 101.99 पर आ गया।

महत्वपूर्ण ख़बर

मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर किया नमन

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि देश को परमाणु शक्ति संपन्न और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में डॉ. कलाम का योगदान अविस्मरणीय है।उनका जीवन और विचार आज भी युवाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती देवी दुर्गा भाभी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दुर्गावती देवी जी का साहस, त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय एवं प्रेरणादायी रहेगा।

गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 5वें संस्करण का 15 अक्टूबर से शुभारंभ

- भोपाल। पर्यटकों को प्रकृति के बीच रोमांच और सुकून का अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए मंदसौर के गांधीसागर जलाशय के सुरम्य बैकवाटर्स पर 'गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट' के पांचवें संस्करण का शुभारंभ 15 अक्टूबर को किया जा रहा है। एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा लल्लूजी एंड सन्स एवं इवोक कैंपिंग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। चंबल नदी के शांत जल विस्तार और प्राकृतिक परिवेश के बीच यह आयोजन साहसिक और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

कहीं 8 से 10 घंटे बिजली गुल तो कहीं रातभर अंधेरे में डूबे गांव; भोपाल, सीहोर, बैतूल में चक्काजाम और प्रदर्शन

भोपाल, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, विदिशा और नर्मदापुरम सहित कई जिलों में ग्रामीणों ने अघोषित बिजली कटौती के विरोध में चक्काजाम

भोपाल। प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। कहीं आठ से दस घंटे बिजली गुल रहने की शिकायत है, तो कहीं रातभर गांव अंधेरे में डूबे रहते हैं। न तो उनकी सुनवाई हो रही है और न ही निर्बाध आपूर्ति मिल रही है। इससे सिंचाई प्रभावित होने से जहां फसलों पर संकट छाने लगा है, वहीं घरेलू कामकाज से लेकर बच्चों की पढ़ाई, त्योहार की तैयारियां सबकुछ प्रभावित होने लगा है। ऐसे में उनका गुस्सा अब सड़कों पर फूटने लगा है।

भोपाल, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, विदिशा और नर्मदापुरम में किसान व ग्रामीण तो बिजली कंपनी के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में नाराज ग्रामीणों ने कई जगह चक्काजाम कर यातायात रोका, बिजली कंपनी के कार्यालयों का घेराव किया और धरना दिया। हालांकि इसे लेकर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने अजीत तर्क दिया।

उनका कहना है कि शहरी क्षेत्र में त्योहार के दौरान निर्बाध आपूर्ति के लिए जबलपुर से निर्देश मिले थे। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति नहीं हुई है। उन्होंने अगले एक से दो दिन में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब दस गांवों में तो रातभर बिजली ही नहीं रहती। वहीं, सीहोर जिले में पिछले 5 दिन से शाम 6 से 8 बजे और फिर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली कटौती हो रही है। आष्टा, जावर, इछावर, बुधनी और सीहोर में तो इसे लेकर विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं। इछावर के भाऊखेड़ी और कोठरी में चक्काजाम किया गया था, जबकि जावर में बिजली कंपनी के कार्यालय पर तालाबंदी की गई थी।

ग्रामीणों ने बैतूल-आमला मार्ग पर किया चक्काजाम

बैतूल जिले के मोरडोंगरी में मंगलवार रात ग्रामीणों ने बैतूल-आमला मार्ग पर चक्काजाम किया। करीब तीन घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। आठनेर, भैंसदेही और भीमपुर में भी रात के समय दो से तीन घंटे बिजली बंद रहने की शिकायत है। किसानों के अनुसार, दिन में छह से सात घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे सिंचाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है।

किसानों ने घेरा बिजली कंपनी कार्यालय

विदिशा जिले के नटेरन में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने बिजली कंपनी का घेराव किया, जबकि सिरोंज में ग्रामीणों ने चक्काजाम किया। बुधवार को कुरवाई में कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सुधार की मांग की। इसी तरह नर्मदापुरम जिले के आरी गांव में किसानों ने मंगलवार रात बिजली उप केंद्र पर एक घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। किसान केशव साहू ने बताया कि भार नियंत्रण और रखरखाव के नाम पर कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इससे फसल सूखने की कगार पर है।

अधीक्षण यंत्री और पूर्व विधायक भिड़े

राजगढ़ जिले में बिजली कटौती के विरोध में आठ अक्टूबर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। करेड़ी में खुजनेर-राजगढ़ मार्ग पर दो बार चक्काजाम किया गया। काचरी, सिलपटी ग्रिड और काल्याखेड़ी जोड़ पर भी ग्रामीणों ने रास्ता रोका। 13 अक्टूबर को ढाबला जोड़ पर जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग करीब एक घंटे जाम रहा। इस दौरान पूर्व विधायक बापूसिंह तंवर और अधीक्षण यंत्री राकेश मेहरा के बीच फोन पर नोक-झोंक तक हुई। अधिकारी के यह कहने पर कि कटौती उनके हाथ में नहीं है, तंवर ने गहरी नाराजगी जताई थी। इसे लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और गेट पर बैठकर भजन गाए।

इनका कहना है

त्योहार के दौरान शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए जबलपुर से निर्देश जारी किए गए थे। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे कटौती की स्थिति बनी है। अगले एक से दो दिनों में आपूर्ति व्यवस्था सामान्य हो जाएगी।

अंकुर सेठ
जनरल मैनेजर (ओएंडएम भोपाल)
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

फ्लाई ऐश से भरे बल्कर वाहन की टक्कर से एक की मौत

सड़क पर उतरे गुस्साए ग्रामीण, लगाया जाम

खंडवा : पुनासा-सनावद मार्ग पर हरवंशपुरा गांव के पास बीती रात राखड़ से भरे बल्कर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत के बाद गुरुवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हादसे से आक्रोशित हरवंशपुरा सहित आसपास के गांवों के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया।

ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने और हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, बीती रात पुनासा-सनावद मार्ग पर हरवंशपुरा गांव के पास राखड़ के बल्कर की टक्कर से एक व्यक्ति की जान चली गई थी। घटना के बाद से ही क्षेत्र के ग्रामीणों में नाराजगी थी। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा

चक्काजाम के कारण पुनासा-सनावद मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगने से वाहन चालकों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। चक्काजाम समाप्त कराने और यातायात बहाल करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किए गए।

ग्रामीणों की प्रमुख मांग मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने और हादसे के मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की है। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

खेत में लगी आग की चपेट में आकर महिला और बकरियां झुलसीं

गुना। जिले के आरोन क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर में एक खेत में खड़ी फसल में बुधवार शाम आग लग गई। इससे आग की चपेट में आकर कुछ बकरी और एक महिला झुलस गई। बाद में गुना से आग बुझाने फायर बिग्रेड भेजी गई।

जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को पुलिस ने गुना नपा को आग की सूचना दी। इस पर गुना से आग बुझाने दमकल वाहन भेजा गया। हालांकि तब तक बकरी और महिला आग की चपेट में आकर झुलस गए थे।

देर रात तक बुझाई आग

देर रात तक आग बुझाने का कार्य किया गया। मामले में नगर परिषद सीएमओ आरोन दिनेश सोनी ने बताया कि उनका दमकल वाहन कई दिनों से खराब है, जो गुना में मरम्मत के लिए भेजा गया है।

10 पुरानी दमकल के भरोसे ग्रामीण

फिलहाल एक छोटे दमकल से काम चला रहे हैं। खराब दमकल करीब 10 वर्ष पुराना होकर आए दिन खराब होता रहता है। नए दमकल वाहन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, जल्द ही नए दमकल वाहन का प्रबंध करेंगे।

दमकल वाहन खराब होने से मचा हड़कंप

दुष्कर्म पीड़िता पर गवाही बदलने का दबाव डालने और परेशान करने पर आरोपी के पिता को भी भेजा जेल

इंदौर। दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद बेटे को बचाने के लिए उसके पिता पर पीड़िता को धमकाने और गवाही बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगा है।

खजराना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 48 वर्षीय एजाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी लगातार पीड़िता को कोर्ट में गवाही और साक्ष्य बदलने के लिए परेशान कर रहा था।

आरोपी अब्दुल अजीज जेल में बंद है

एडीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, 18 अप्रैल को अब्दुल अजीज के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी अब्दुल अजीज जेल में बंद है। आरोप है कि इसके बाद उसके पिता एजाज ने पीड़िता पर गवाही और साक्ष्य बदलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

पीड़िता को लगातार परेशान किए जाने की शिकायत पर धमकाने का अलग से खजराना थाने में नया प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने एजाज पुत्र महबूब खान निवासी हुसैनी चौक, अशरफी नगर, खजराना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

मुंबई की फ्लाईट में बैठने से पहले लापता युवती और दो साथी को रोका

इंदौर : इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में सवार होने से ठीक पहले एक युवती और दो युवकों को रोक लिया गया। आलीराजपुर जिले के जोबट थाने में युवती के लापता होने की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस को उनकी यात्रा की सूचना मिली थी। पुलिस की सूचना के बाद सीआईएसएफ ने कार्रवाई करते हुए तीनों को रोककर पुलिस के हवाले कर दिया।इंडिगो की फ्लाइट रात 10.30 बजे इंदौर से मुंबई रवाना होने वाली थी। उड़ान से पहले सूचना मिली कि जोबट निवासी हिमानी राठौर दो युवको रेहान मकरानी और सावन के साथ मुंबई जाने की तैयारी में है। उस समय विमान में यात्रियों की बोर्डिंग चल रही थी। तीनों एयरोब्रिज तक पहुंच चुके थे। तभी सीआईएसएफ की टीम उन्हें रोककर वापस टर्मिनल में ले आई और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल युवति की गुमशुदगी की सूचना जोबट थाने में दर्ज कराई गई थी और पुलिस युवती की तलाश कर रही थी।पुलिस को युवती के मुंबई जाने की सूचना मिली थी।

सुरक्षित मातृत्व सेवाओं से मातृ मृत्यु दर शून्य करने पर हुआ मंथन

भोपाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा यूएनएफपीए मध्यप्रदेश के सहयोग से सुमन रोडमैप 2030 झ देखभाल की निरंतरता में तेजी विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, उच्चजोखिमवालीगर्भावस्थाओं की पहचान एवं प्रबंधन, प्रसव कक्षों में गुणवत्ता सुधार, प्रसूति संबंधी जटिलताओं के प्रभावी प्रबंधन तथा मातृ मृत्यु निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला का उद्देश्य सुमन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को जिला स्तर पर प्रभावी कार्ययोजनाओं में परिवर्तित कर प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना तथा रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु को शून्य करना है। एनएचएम मध्यप्रदेश एवं यूएनएफपीए ने इस दिशा में जिलों को तकनीकी एवं कार्यक्रम संबंधी सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

रबी फसलों के बीज का पर्याप्त भण्डारण

भोपाल। किसानों को आगामी रबी मौसम के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज का पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध है। जिलों में शासकीय एवं अन्य अधिकृत संस्थाओं के पास उपलब्ध है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिलों में बीज की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है। किसानों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार बीज की पर्याप्त उपलब्धता है।

किसानों से आग्रह है कि वे अधिकृत विक्रय केन्द्रों एवं संबंधित सहकारी संस्थाओं से प्रमाणित बीज क्रय कर सकते हैं। बीज खरीदते समय टैग, बिल एवं बीज की वैधता जांच कर लें। किसी भी प्रकार की अनियमितता या निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बीज विक्रय होने पर संबंधित जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दें।

जिलों में मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में 91452 क्विंटल, शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों में 12403 क्विंटल, बीज संघ में 652739 क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगम में 255718 क्विंटल, अन्य अधिकृत संस्थाओं में 190839 क्विंटल इस प्रकार संस्थागत में 1203191 क्विंटल एवं निजी बीज संस्थाओं में 2548843 क्विंटल उपलब्ध है। इस प्रकार कुल 3751994 (सैतींस लाख इक्यावन हजार नौ सौ चौरान्वे) क्विंटल चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर, गेहूं एवं जौ बीज उपलब्ध हैं।

गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरी करने के लिए बना चोर

रीवा के ब्यूटी पार्लर में घुसकर डेढ़ लाख रुपये के प्रोडक्ट उड़ाए

रीवा। सिरमौर चौराहे पर स्थित ब्यूटी पार्लर में हुई चोरी का अमहिया थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 18 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.55 लाख रुपये का सामान बरामद किया है।

पकड़ा गया आरोपी इरफान अंसारी पिता रफीक अंसारी, निवासी तरहटी, थाना सिटी कोतवाली है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की डिमांड पूरी करने के लिए चोरी की थी।

गत 12-13 अक्टूबर की रात हुई थी वारदात

सिरमौर चौराहे स्थित ब्यूटी पार्लर में 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात चोरी हुई थी। पार्लर से करीब 1.50 लाख के ब्यूटी प्रोडक्ट और उपकरण पार हो गए थे। शिकायत पर अमहिया टीआई मनोज गौतम के नेतृत्व में टीम ने जांच शुरू की और बुधवार को आरोपी को पकड़ लिया।

क्या-क्या बरामद हुआ

पुलिस ने आरोपी के पास से प्रोफेशनल मेकअप किट, फेशियल मशीन, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर, स्किन केयर प्रोडक्ट और 5 हजार का एक मोटर पंप बरामद किया है। कुल बरामद माल की कीमत 1.55 लाख आंकी गई है। थाना प्रभारी मनोज गौतम ने बताया कि आरोपी ने प्रेमिका की मांग वाला एंगल बताया है, लेकिन पुलिस इस कोण की गहराई से जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं।

पाइल्स के ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत, कटनी में परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन देने का आरोप

कटनी। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने और उसमें युवक की मौत होने का आरोप लगा है। स्वजनों ने अस्पताल में हंगामा किया।

पुलिस की समझाइश के बाद चिकित्सकों की टीम व तहसीलदार की मौजूदगी में पीएम कराया गया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार मघई मंदिर के पीछे रहने वाले बीएन मिश्रा के पुत्र अंशुल मिश्रा 35 साल को पाइल्स की बीमारी थी। जिसको लेकर उसने नगर के गुरुकृपा अस्पताल के चिकित्सक डॉ. पीके सहाय से संपर्क किया था। अंशुल के पिता ने बताया कि चिकित्सक ने उनको बेटे का ऑपरेशन जल्द कराने की सलाह दी थी और उनके बताए अनुसार ही बेटे की विभिन्न जांच कराई गई। जिसके लिए जबलपुर से भी रिपोर्ट मिली और उसमें सभी चीजें नार्मल थीं।

स्वजनों का कहना है कि मंगलवार की शाम को अस्पताल में डॉ. सहाय व उनकी टीम ने अंशुल का ऑपरेशन शुरू किया और इस बीच ऑपरेशन थियेटर की टेबिल में ही उसकी मौत हो गई। उनका आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन ने उनको जानकारी देने के स्थान पर पुलिस को पहले सूचना दी और शव को पीएम के लिए भिजवा दिया।

स्वजनों का आरोप था कि ऑपरेशन के दौरान किसी गलत इंजेक्शन के लगने से अंशुल की मौत हुई, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि हृदयगति रूक जाने के कारण युवक की मौत हुई।

रात को ही अस्पताल पहुंचे स्वजन

युवक की मौत के बाद आक्रोशित स्वजन रात को निजी अस्पताल गेट में एकत्र हो गए और हंगामा करने लगे। मौके पर कोतवाली पुलिस भी पहुंची और स्वजनों को मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। जिसके बाद लोग शांत हुए। वहीं बुधवार को भी स्वजन घटना को लेकर आक्रोशित रहे और मामले की जांच कराने की मांग की। स्वजनों की मांग थी कि चिकित्सकों का पैनल बनाकर पीएम कराया जाए और उसकी वीडियोग्राफी भी हो, दोषी पाए जाने पर चिकित्सकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। उनकी मांग पर चिकित्सकों की टीम और तहसीलदार की मौजूदगी में पीएम कराया गया है। साथ ही परिवार को पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम किया है और मामले की जांच कर रही है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी-85, सेक्टर-8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच-41ए, अबुल फज़ल एन्क्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली-110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No : DELMUL/2012/47011 | Email :timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायलय के अधीन होंगे।